▶▶ कृषि ▶▶ विश्लेषण ▶▶ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/—रू.

माघ—फाल्गुन 2079, फरवरी 2023

विकास प्रेरक सर्वस्पर्शी बजट

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी मेला

कानपुर, उत्तर प्रदेश

सचित्र झलक

बोकारो, झारखंड

स्वावलंबी भारत अभियान

(उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन)

Entrepreneurship Encouragement Conferences

नर्मदापुर, मध्य प्रदेश

स्वदेशी पत्रिका

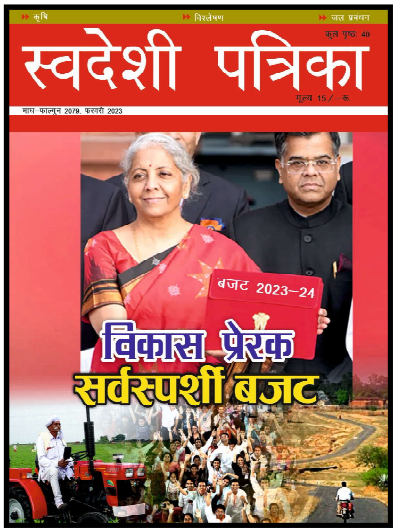

वर्ष–31, अंक–2
माघ–फाल्गुन 2079 फरवरी 2023

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

अनुक्रम

आवरण कथा – पृष्ठ–08

विकास प्रेरक सर्वस्पर्शी बजट

प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

06 आजकल
दूध का धुला नहीं है हिन्डनबर्ग ..... डॉ. अश्वनी महाजन

11 बजट 2023–24
बजट से मिला बैंकिंग कारोबार को बूस्टर डोज ..... अनिल तिवारी

13 बजट 2023–24
अमृत बेला का स्वदेशी बजट ..... डॉ. धनपत राम अग्रवाल

15 बजट 2023–24
बजट में सबके सपनों का सम्मान ..... विक्रम उपाध्याय

17 बजट 2023–24
अमृतकाल का पहला बजट ..... अनिल जावलेकर

19 बजट 2023–24
'हर घर नल से जल' योजना का विस्तार ..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

21 बजट 2023–24
सबकी उम्मीदों पर खरा है बजट ..... वैदेही

23 बजट 2023–24
विकसित राष्ट्र की आधारशिला रखने वाला बजट ..... प्रहलाद सबनानी

25 विश्लेषण
कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर है अभी ..... के.के. श्रीवास्तव

27 मुद्दा
बढ़ते विदेश पलायन से उपजी आर्थिक चुनौती ..... देविन्दर शर्मा

29 बीच–बहस
हरित अनुबंध पत्र (ग्रीन बॉन्ड) ..... विनोद जौहरी

31 अवलोकन
तेजी से बदलता ग्रामीण भारत ..... शिवनंदन लाल

पाठकनामा

अमृतकाल का पहला बजट

देश का बजट अब सामान्य जनता के सामने पेश कर दिया गया है। इस बजट को प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री ने मध्यम वर्ग को खास रूप से साधते हुए सबके विकास की बात की है। टैक्स में राहत देने के उद्देश्य से पांच लाख तक की राशि को कर से मुक्त रखा है। यह मध्यम वर्ग के लिए काफी राहत भरी खबर कहीं जा सकती है। लेकिन बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। बेरोजगारी को किस तरह कम किया जाएगा, जिससे आम जनता को राहत मिले, यह चिंतन का विषय है। बजट के प्रस्तुत होने के बाद से विश्व बाजर मार्केट के शेयर धराशायी होता गया। परिणामस्वरुप कई आवश्यक वस्तुओं की कीमत में इजाफा हो गया है। अभी जबकि फाल्गुनी मौसम में कई सब्जियां सस्ती, जो शायद मध्यम और गरीब जनता की थाली तक सहज पहुँच रही है, लेकिन मौसम के बदलाव के साथ इन वस्तुओं की कीमत में इजाफा होने की संभावना बढ़ती जाएगी।

सामान्य जन जीवन के साथ जुड़ी कई वस्तुओं की कर दरों में भी कमी राहत भरी है। डिजिटलीकरण पर जोर तो दिया गया है लेकिन उसके उपयोग के लिए किए जाने वाली वस्तुओं, डाटा संसाधनों को महंगाई से लोगों की जेब पर भार पड़ेगा। ऐसे में यह कार्य कैसे किया जा सकेगा? कृषि आमदनी को बढ़ाकर ग्रामीण जन जीवन को शहरी जन जीवन के समतुल्य खड़ा करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव का यह पहला बजट किसानों, महिलाओं व वृद्धों के कल्याण के साथ–साथ देश के विकास पर केंद्रित है।

डॉ. पराक्रम सिंह, धुंधरी, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। हर वर्ग का सपना पूरा होगा। यह बजट गरीब, मध्यम वर्ग, किसान सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

बजट किसानों, महिलाओं, सीमांत वर्गों और मध्यम वर्ग को सहायता प्रदान करने की प्राथमिकता के साथ, विकास और कल्याण पर केंद्रित है। इस जनहितैषी काम के लिए वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को बधाई।

राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत

बजट–2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है। मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा।

अमित शाह, गृहमंत्री, भारत

ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और छोटे उद्योगों पर ध्यान देने के साथ बजट विकास को गति देगा और आयकर ढ़ांचे में बदलाव से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

विकास पर फोकस, मध्यम वर्ग को राहत

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद के समक्ष 'अमृत काल' का पहला पूर्ण बजट और मोदी–02 सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। उम्मीद के मुताबिक, अति धनी सहित मध्यम वर्ग के लिए, आयकर का बोझ (नई कर व्यवस्था में) कम हो गया है, जिसका कुल राजस्व पर प्रभाव 37,000 करोड़ रुपये पड़ेगा। नई आयकर प्रणाली करदाताओं को कम कर बोझ के साथ रिटर्न दाखिल करने में आसानी के मामले में राहत दे सकती है; लेकिन इसका आयकरदाताओं द्वारा की जा रही बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आज के दौर में जहां जीएसटी बजट के दायरे से बाहर हो गया है; और कॉरपोरेट कराधान में किसी तरह के बदलाव की संभावना न के बराबर है, आर्थिक विश्लेषकों की नजर में सरकारी खर्च का आवंटन ज्यादा है। निस्संदेह, सरकारी व्यय का आवंटन सरकार की नीतियों का आईना होता है; और इस बजट में यह पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है।

बजट में बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, हरित विकास, शिक्षा और डिजिटलीकरण के लिए आवंटन सराहनीय है। मिलेट्स यानि मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में मिलेट्स को बढ़ावा देना, कृषि ऋण में बढ़ोतरी, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों पर ध्यान देना, सहकारिता को प्रोत्साहन आदि इस बजट के प्रमुख आकर्षण हैं। बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) को बढ़ावा देते हुए डेयरी, मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रावधान बजट में शामिल किये गये हैं। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करना एक स्वागत योग्य कदम है। यह सभी कृषि और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देगा। नई घोषणा के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट' से 'एस्पिरेशनल ब्लॉक' की ओर बढ़ते हुए, पिछड़े ब्लॉकों में ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए आवंटन अधिक समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का एक और प्रयास है। पिछले साल के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, प्रभावी पूंजीगत व्यय (पूंजी निर्माण के लिए राज्य सरकारों को समर्थन सहित) का हिस्सा बढ़ाकर 13.7 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रकार की परिसंपत्तियों के निर्माण में वृद्धि होगी। 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय रेलवे के लिए, 7500 करोड़ रुपए के लॉजिस्टिक सहित विभिन्न प्रकार के पूंजीगत व्यय का प्रावधान इस बजट को खास बनाता है। इतना पूंजीगत व्यय न केवल मात्रा के लिहाज से, बल्कि हाल के दशकों में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भी एक रिकॉर्ड है।

बजट में एक और स्वागत योग्य फोकस एमएसएमई क्षेत्र है। मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी का विस्तार करना, उन मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को राहत देना जो अपने अनुबंधों को पूरा नहीं कर सके, कारीगरों, जो सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं को सशक्त बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना स्वागत योग्य कदम हैं। ग्रीन ग्रोथ पर जोर इस बजट की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नवीकरणीय ऊर्जा, गोबर्धन, ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट आदि जैसे प्रावधानों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 2070 तक 'शुद्ध शून्य' के भारत के संकल्प के संकेत के रूप में माना जा सकता है। सरकार पिछले कुछ समय से पर्यटन पर ध्यान दे रही है। कनेक्टिविटी में सुधार के साथ ही इस बजट में इस क्षेत्र में स्वरोजगार और कौशल निर्माण सहित कई प्रावधान हैं।

हालांकि, यह उम्मीद की गई थी कि इस बजट में विनिर्माण पर जोर दिया जाएगा, परंतु इस दिशा में पर्याप्त प्रयासों की कमी है। आज देश चीन से अभूतपूर्व आयात और व्यापार घाटे के दौर से गुजर रहा है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं जा सका। अब ज़रूरत इस बात की है कि अंतिम और साथ ही मध्यवर्ती उत्पादों दोनों पर टैरिफ की बढ़ोतरी की जाए, जहां भारत में क्षमता उपलब्ध है। वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, कुल व्यय लगभग 42 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसकी तुलना में इस साल करीब 45 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान (बजट अनुमान) रखा गया है, यानी महज 7 फीसदी की बढ़ोतरी। शायद राजकोषीय घाटे को 5.9 प्रतिशत तक सीमित करने के उद्देश्य से व्यय को सीमित किया गया है, हालांकि पूंजीगत व्यय पर राजकोषीय संतुलन का प्रभाव महसूस नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और एमएसएमई पर ध्यान देने के साथ बजट विकासोन्मुख है, जिसमें समाज के सभी वर्गों की बेहतरी का पर्याप्त ध्यान रखते हुए भारत को दुनिया के समक्ष बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का रास्ता दिखाई देता है। मध्यम वर्ग द्वारा बचत, जो कि सरकार के उधार और पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, को बढ़ावा देने के लिए कर व्यवस्था में सुधार के साथ–साथ उन उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने चाहिए, जिससे कि चीन के आयात पर अंकुश लगे और देश के विनिर्माण को बढ़ावा मिले।

दूध का धुला नहीं है हिन्डनबर्ग

हिन्डनबर्ग रिसर्च नाम की फर्म ने अडानी समूह के खिलाफ अपनी हालिया रिपोर्ट में कुछ गंभीर आरोप लगाये हैं, जिसमें धोखाधड़ी और गलत तरीके से शेयर कीमतों को प्रभावित करने के आरोप भी शामिल है। उसके बाद अड़ानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आ गई है। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के कारण शेयरों में गिरावट के कारण गौतम अड़ानी की निवल संपत्ति 30 अरब डालर यानि 2.5 लाख करोड़ रूपये घट चुकी है। यही नहीं अड़ानी समूह के कुल मूल्य में 65 अरब डालर यानि 5 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा का नुकसान अभी तक हो चुका है।

गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गौतम अड़ानी समूह की कंपनियों का तेजी से विस्तार हुआ है। विपक्षी दलों द्वारा यह भी अरोप लगाया जाता रहा है कि सरकार द्वारा इस समूह को जरूरत से ज्यादा समर्थन दिया गया है। हिन्डनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद विपक्षी दलों ने भी अड़ानी समूह पर हमला बढ़ा दिया है।

हिन्डनबर्ग की रिपोर्ट की सत्यता क्या है, इसके बारे में अभी टिप्पणी करना संभव नहीं है, लेकिन, चूंकि हिन्डनबर्ग की रिपोर्ट मात्र अड़ानी समूह के बारे में ही आई है, इसलिए इन गलतियों या धोखाधड़ी के बारे में केवल अड़ानी समूह को ही कटघरे में खड़ा करना कितना सही है, यह समझना होगा। क्या जो आरोप अड़ानी समूह पर लगाये गये है वहीं आरोप क्या अन्य समूहों पर भी आ सकते हैं? इस पर भी विचारा होना चाहिए।

क्या है हिन्डनबर्ग रिसर्च और उनके आरोप

हिन्डनबर्ग रिसर्च नाथन एंडरसन द्वारा स्थापित एक फोरंसिक वित्तीय शोध फर्म है, जो शेयर (अंश), क्रेडिट और डेरिवेटिव का विश्लेषण करती है। कहा जा रहा है कि इससे पहले यह 16 कंपनियों की गलतियों और धोखाधड़ियों का खुलासा कर चुकी है। जिसमें इलैक्ट्रिक ट्रक कपंनी निकोला कारपोरेशन और 'एलॉन मस्क' द्वारा ट्विटर के अधिग्रहण के संदर्भ में, ट्विटर के बारे में खुलासे शामिल है। यानि हिन्डनबर्ग रिसर्च द्वारा अड़ानी समूह के बारे में खुलासा पहला ऐसा खुलासा नहीं है।

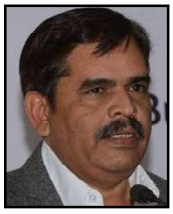

विदेशी एजेंसियों द्वारा भारतीय उद्यमों पर किये गये हमलों से इन कंपनियों को बचाना होगा। यदि किसी भी प्रकार की गलती इन कंपनियों द्वारा की भी जाती है तो उसे भी देश के कानूनों के अनुसार दुरूस्त करना जरूरी होगा।

– डॉ. अश्वनी महाजन

समझना होगा कि हिन्डनबर्ग रिसर्च एक व्यवसायिक फर्म है, जिसका काम 'शॉर्ट सैलिंग' का है। शेयर बाजार की शब्दावली में 'शॉर्ट सैलिंग' उस स्थिति को कहते हैं, जब कोई फर्म या व्यक्ति अपने अधिकार में शेयरों से ज्यादा शेयरों की बिक्री करती है। ऐसे में सौदे के निपटारे के समय 'शॉर्ट सैलर' को उस समय के भाव के अनुसार निपटान करना पड़ता है। अपने पास शेयरों से ज्यादा शेयरों को बेचने (यानि शॉर्ट सैलिंग) विक्रेता स्वभाविक रूप से इस मान्यता पर चलता है कि भविष्य में शेयर का दाम कम होगा और ऐसे में पहले ऊंची कीमत पर शेयर बेचने पर उसे निपटान के दिन फायदा होगा। यानि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हिन्डरबर्ग रिसर्च, जिसके हित कंपनियों के शेयरों की कीमतों में गिरावट के साथ जुड़े हैं, ऐसे तथाकथित खुलासों के माध्यम से धन कमाने के उद्देश्य से भी जुड़े हुए हैं। यानि यह 'हितों के टकराव' का मामला बनता है।

दिलचस्प बात यह है कि इसी हिंडनबर्ग को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने जुलाई 2022 में एबिक्स, एक कंपनी जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च शॉर्ट पोज़िशन में थी, के आवेदन पर ट्वीट वापस लेने के लिए आदेश दिया था, जिसका प्रतिकार हिन्डनबर्ग नहीं कर पाया। एबिक् रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए गूगल खोज परिणामों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था।

क्या करती है अडानी की कंपनियां

अडानी विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य लोजेस्टिक, खनन, धातु, ऊर्जा समेत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में देश का सबसे तेजी से बढ़ता समूह बन चुका है। अडानी की कंपनियों में अड़ानी पोर्ट्स एवं एससीजेड़, अड़ानी पावर, अड़ानी ट्रांसमिशन, अड़ानी एंटरप्राइसेस, अड़ानी टोटल गैस, अड़ानी विलमार्क सरीखी कंपनियां शामिल है। अगर केवल अडानी एयर पोर्ट्स की बात की जाए तो मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेगलूरू, जयपुर, गुवाहटी, तिरूवंतपुरम् समेत कई एयरपोर्टो का विकास एवं संचालन अडानी समूह द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में शुरू अडानी ग्रीन एनर्जी नाम की कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में सोलर पैनल और अन्य उपकरण बनाये जा रहे हैं। जिससे देश की निर्भरता चीन समेत दूसरे मुल्कों पर घटने लगी है। अडानी पोर्ट्स एवं एससीजेड द्वारा कई बंदरगाहों को निर्माण एवं संचालन हो रहा है। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से एक बड़ा प्रयास किया गया है और सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग को लगभग 60 हजार करोड़ रूपये के उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन देने की घोषणा कर चुकी है। उसी के तहत ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही अडानी समूह द्वारा बनाये गये सेमीकंडक्टर बाजार में उतर जायेंगे। यानि देखा जाए तो अडानी समूह की सभी कंपनियां देश में मैन्यूफेक्चिरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वास्तविक परिसंपत्तियों का निर्माण कर रही हैं।

क्या देश को हो सकता है नुकसान?

कुछ लोगों का यह मानना है कि हिंडनबर्ग द्वारा अडानी समूह की बदनामी और उसके कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट के कारण मात्र अडानी समूह ही नहीं बल्कि पूरे देश की साख पर बट्टा लग सकता है और विदेशी निवेशकों को यह भारत से विमुख कर सकता है। लेकिन समझना होगा कि हितों के टकराव से ग्रस्त किसी एजेंसी की रिपोर्ट को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। भारत इस समय दुनिया भर के निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारत के बड़े बाजार, विश्व की सबसे ऊंची संवृद्धि दर, विविध क्षेत्रों में प्रगति, मैन्यूफेक्चरिंग क्षेत्र में भारत सरकार के प्रभावी प्रयासों के कारण देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ता जा रहा है। आज देश में विकास की समर्थक सरकार, राजनीतिक स्थायित्व और हर क्षेत्र में प्रगति व विविध प्रकार की अनुकूलता का वातावरण है। लोकतंत्र और न्यायसंगत व्यवस्था, भारत के प्रति आकर्षण का एक मुख्य कारण है। इसलिए यह समझना कि हितों के टकराव से ग्रस्त किसी एजेंसी की एक कंपनी को निशाने पर लेकर रिपोर्ट से भारत का निवेश वातावरण प्रभावित हो जायेगा, सही नहीं होगा।

हिंडनबर्ग द्वारा अडानी समूह की बदनामी और उसके कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट के कारण मात्र अडानी समूह ही नहीं बल्कि पूरे देश की साख पर बट्टा लग सकता है और विदेशी निवेशकों को यह भारत से विमुख कर सकता है।

परिसंपत्ति निर्माण बनाम कैश बर्निंग

आज देश और दुनिया में दो प्रकार के व्यवसायिक मॉडल चल रहे हैं। एक है, परंपरागत परिसंपत्ति निर्माण का मॉडल, जिसमें उत्पादन इकाईयों, इंफ्रास्ट्रक्चर और विविध प्रकार के लोजिस्टिक का निर्माण होता है और उसके माध्यम से उत्पादन क्षमता एवं जीडीपी बढ़ाई जाती है। अडानी समूह के द्वारा व्यवसाय का यह मॉडल अपनाया गया है। इसके कारण देश में विविध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। दूसरी तरफ व्यवसाय का एक अन्य मॉडल चल रहा है, जिसे कैश बर्निंग मॉडल कहते है। इसमें उपभोक्ताओं को विविध प्रकार के डिस्काउंट के माध्यम से अपने बाजार का विस्तार किया जाता है और उसके आधार पर फर्म का वैल्यूवेशन बढ़ाकर निवेशकों को आकर्षित कर उनसे निवेश लिया जाता है। वैश्विक स्तर पर अमेजॉन, भारत में पेटीएम, जोमेटो, नाईका, फ्लिपकार्ट सरीखी अनेक कंपनियां इस बिजनेस मॉडल को अपनाकर आगे बढ़ रही हैं। हाल ही में इनमें से कई कैश बर्निंग कंपनियों द्वारा 'सेबी' के माध्यम से आईपीओ जारी कर आम निवेशकों से धन लिया गया। इनमें से अधिकांश निवेशकों का 40 से लेकर 70 प्रतिशत तक धन डूब चुका है।

समझना होगा कि जब भारत के अनेक धनाढ़य लोग यह मानकर कि भारत में रहना लाभप्रद नहीं है, अपनी संपत्तियां बांधकर विदेशों को स्थानांतरित हो गये और कुछ धनाढ़य लोगों ने भारत में ही रहकर उद्यम बढ़ाने का निर्णय लिया तथा तेजी से विस्तार भी किया, तो चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, महेंद्रा हो, विरला समूह की कंपनियां हो, आईटीसी हो, अथवा एलएंडटी, इन समूहों और कंपनियों ने भारत की ग्रोथ यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से ये कंपनियां कैश बर्निंग व्यवसायों से बेहतर काम कर रही है। ऐसे में विदेशी एजेंसियों द्वारा भारतीय उद्यमों पर किये गये हमलों से इन कंपनियों को बचाना होगा। यदि किसी भी प्रकार की गलती इन कंपनियों द्वारा की भी जाती है तो उसे भी देश के कानूनों के अनुसार दुरूस्त करना जरूरी होगा। ❑❑

विकास प्रेरक सर्वस्पर्शी बजट

वर्ष 2023–24 बजट में देश के सभी वर्गों की अपेक्षाओं को यथोचित दृष्टिगत रखते हुए आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य साधे रखा गया है। सप्तऋषि की भांति सात मौलिक प्राथमिकताओं यथा समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, आधारिक रचनाओं व निवेश, अन्तर्निहित क्षमताओं के विकास, युवा, शक्ति हरित विकास तथा वित्तीय क्षेत्र पर केन्द्रित बजट में उच्च प्रौद्योगिकी विकास का भी ध्यान रखा गया है। वरिष्ट नागरिकों के लिए बचत सीमा को दोगुना कर महिला सम्मान बचत पत्र भी एक सराहनीय पहल है। सामान्य नागरिक अपनी अर्जित आय का यथोचित उपयोग कर सके व अपनी बचतों का इच्छानुरूप निवेश कर सकें, इस हेतु एक वैकल्पिक आयकर संरचना भी प्रस्तावित की गई है। अब कर बचाने हेतु अपनी बचतों को सरकारी योजनाओं में दीर्घकाल तक अवरूद्ध रखने को बाध्य नहीं हो इस हेतु एक वैकल्पिक नवीन कर योजना प्रस्तावित की गई है। इससे मध्यमवर्गी कर दाता अपनी बचतों को अधिक लाभप्रद व बेहतर लोचशीलता वाले निवेश अवसरों में निवेश कर सकेंगे। इससे देश में बचत व निवेश का स्वतःस्फूर्त वातावरण बनेगा। कृत्रिम बुद्धिमता, नई पीढ़ी के कौशल, 5 जी, आदि के साथ ही पर्यावरण सुधार, कृषि, पशुपालन व मत्स्यिकी आदि विकासोन्मुख बजट उपायों से समग्र विकास की सुदृढ़ रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

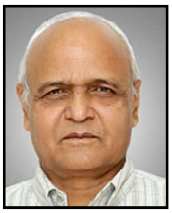

सप्तऋषि की भाँति सात मौलिक प्राथमिकताओं यथा समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, आधारिक रचनाओं व निवेश, अन्तर्निहित क्षमताओं के विकास, युवा, शक्ति हरित विकास तथा वित्तीय क्षेत्र पर केन्द्रित बजट में उच्च प्रौद्योगिकी विकास का भी ध्यान रखा गया है।

– प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

कृषि व सहकारिता हेतु समुचित प्रावधान

कृषि क्षेत्र में पहले से ही पीएम किसान योजना के अन्तर्गत किसानों को सीधे नकद लाभ मिल रहा है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष में 2.2 लाख करोड़ रू. किसानों के खातों में ट्रांसफर किए हैं। मोटे अनाज के उत्पादन, अनुसंधान व निर्यात में बढ़ोत्तरी के लिए 'श्री अन्न योजना' का प्रस्ताव भी किया है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उसका निर्यात भी बढ़ाना तथा पारंपरिक खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल पर निर्भरता कम करना है। भारत मोटे अनाज के उत्पादन में वैश्विक केन्द्र बने इस हेतु मोटे अनाज पर अनुसंधान पर भी प्रावधान किया है। यह वर्ष (2023) मोटे अनाज का वर्ष भी है।

सरकार कृषि एवं सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने जा रही है। कृषि के संबंध में बजट में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा युवा उद्यमियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप स्थापित करने के लिए 'कृषिवर्द्धक निधि' अर्थात एग्री एक्सीलेरेटर निधि की स्थापना भी प्रस्तावित की गई है। लंबे रेशेदार कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी पीपीपी के माध्यम से क्लस्टर आधारित वैल्यू चेन का निर्माण, हाई वेल्यू बागवानी फसलों के लिए 'आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम' के आरंभ की भी घोषणा की गई है। बजट में कृषि ऋणों को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रु. तक करने की घोषणा भी महत्वपूर्ण है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास

लोक कल्याण की दृष्टि से स्वास्थ्य, शिक्षा व आवास के प्रावधान भी उल्लेखनीय हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से सभी विद्यमान 157 मेडिकल कॉलेजों के पास इतनी ही संख्या में नर्सिंग कॉलेज खोलने के प्रस्ताव की घोषणा की गई है। इससे देश में नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सकेगा। देश में 2047 तक सिकल सेल

एनीमिया के पूरी तरह समाप्त करने के लिए मिशन की शुरुआत प्रस्तावित की गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान व नवाचार के लिए चुनी हुई आईसीएमआर की प्रयोगशालाओं की सुविधा सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को उपलब्ध कराई जाएगी। फार्मास्युटिकल्स के क्षेत्र में नवाचार के उद्देश्य से उत्कृष्टता केन्द्रों के माध्यम से नवीन कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

शिक्षा मंत्रालय को बजट से 1.12 लाख करोड़ रूपये आवंटित किए हैं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें व अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना भी प्रस्तावित है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से बजट में समाज के कमजोर वर्गों, खासकर 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38 हजार 800 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी।

गरीबों को आवास प्रदान करने वाली पीएम आवास योजना की बजट राशि 60 फीसदी बढ़ाकर 79 हजार करोड़ कर दी गई है। देश में 'भविष्य के शहरों' के विकास की दृष्टि से शहरी योजना में सुधार करने तथा म्युनिसिपल बांड निर्गमित करने की छूट का बजट एक अभिनव पहल है। शहरों के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए सरकार 'शहरी अधोसरंचना विकास निधि' की स्थापना करेगी। इस निधि का संधारण राष्ट्रीय आवास बैंक करेगी।

सफाई कर्मियों को राहत व जोखिम मुक्ति

बजट में एक अहम घोषणा मानवीय गरिमा के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सीवेज लाइनों के मेनहोल की सफाई पूरी तरह से मशीनों से ही कराने की है जो एक सराहनीय कदम है। सफाई कामगार कई बार ऐसा करते समय मृत्यु का शिकार हो जाता था।

उन्नत प्रौद्योगिकी विकास पर बल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को बढ़ावा देने के लिए देश के तीन शीर्ष शिक्षा संस्थानों में उत्कृष्टता केन्द्र खोलने की घोषणा की है। यह आज समय की आवश्यक मांग है। इस बजट की अन्य अहम बातों में अब पैन नंबर को ही पहचान का प्रमाण मानने, ई–न्यायालय परियोजना शुरू करने, 5जी सेवाओं के एप्लीकेशन तैयार करने, इंजीनियरिंग कॉलेजों में सौ प्रयोगशालाएं स्थापित करने तथा देश में कृत्रिम हीरा उत्पादन को प्रोत्साहित करना आदि हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल सम्पन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम सम्मिलित किए जाएंगे। कुशल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध् कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।

आधुनिकीकरण के और भी प्रयास

न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए, 7,000 करोड़ रूपये के परिव्यूय से ई–न्यायालय परियोजना का चरण–3 शुरू किया जाएगा। पर्यावरण सुधार हेतु राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने 2030 तक 5 एमएमटी के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऊर्जा–परिवर्तन तथा निवल कार्बन शून्यतम उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता हेतु पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। लद्दाख से नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रूपये के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी।

सूक्ष्म व लघु उद्यमों को सहायता

एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह पहली अप्रैल 2023 से कार्पस में 9,000 करोड़ रुपये जोड़कर क्रियान्वित होगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये के ऋण संपार्श्विक गारंटी से मुक्त हो सकेंगे। ऋण की लागत में भी लगभग 1 प्रतिशत की कमी आएगी। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में दाखिल विभिन्न फॉर्मों के केन्द्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों की त्वरित कार्रवाई के लिए एक केन्द्रीय डाटा संसाधन केन्द की स्थापना की जाएगी।

कारोबारी सुगमता के लिए 39,000 अनुपालनों को हटा दिया गया और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया। सरकारी की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में 42 केन्द्रीय कानूनों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक लाया गया।

युवाओं के लिए प्रशिक्षुवृत्ति

एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरूआत कर कौशलवर्धन हेतु मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्द्धन सक्षम करने, एमएमएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा।

आयकर सुधारः वैकल्पिक कर योजना

करदाता सेवाओं में और सुधार करने के लिए करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फार्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ किया जा रहा है। नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

आयकर में छूट की घोषणा से देश के करीब 40 करोड़ लोगों को फायदा होगा। व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा 5 से बढ़ाकर 7 लाख करने के साथ ही आयकर स्लैब भी 6 से घटाकर पांच कर दिए हैं। नई व्यवस्था के अधीन अब 3 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर या टेक्स नहीं लगेगा, जबकि 3 से 6 लाख तक 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख तक 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख तक 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख तक 20 प्रतिशत तथा 15 लाख से ऊपर की आय वालों को पूर्ववत 30 प्रतिशत आयकर देना होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत आयकर की उच्चतम अधि ाभार की दर 42.74 प्रतिशत को घटाकर अब 37 प्रतिशत कर दी गई है।

बचत के निवेश के बेहतर विकल्प

नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी व्यक्ति को 50 हजार रुपए की मानक कटौती का लाभ देने और परिवार पेंशन से 15 हजार तक कटौती करने का प्रस्ताव है। नई कर व्यवस्था अपनाने वाले कर दाताओं के निवेश विकल्प बढ़ जाने से वे अपनी बचतों को इच्छानुरूप

आज भारत जैसे देश में मांग, उत्पादन व रोजगार वृद्धि के लिए उपभोग में वृद्धि होना भी अच्छा परिणाम ही देगा। बचतों को उत्पादक निवेश की ओर मोड़ने में भी नई कर व्यवस्था बेहतर परिणाम देगी।

बेहतर आय व बिना लॉक इन अवधि वाले निवेश साधनों निवेशित कर सकेंगे। कुछ लोग इस नई योजना के उद्देश्य को नहीं समझ कर यह प्रचारित कर रहे हैं कि इससे घरेलू बचत प्रभावित होगी। आज भारत जैसे देश में मांग, उत्पादन व रोजगार वृद्धि के लिए उपभोग में वृद्धि होना भी अच्छे परिणाम ही देगी। बचतों को उत्पादक निवेश की ओर मोड़ने में भी नई कर व्यवस्था बेहतर परिणाम देगी।

बचत संवर्द्धन हेतु योजना की सीमा दोगुनी व महिला सम्मान बचतपत्र

इस बजट में वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 15 लाख रूपये से बढ़ाकर 30 लाख रूपये करने का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही एकाकी वरिष्ट खाता धारकों के लिए भी जमा राशि की सीमा को दो गुना कर दिया है। अब व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ नागरिक 9 लाख रूपये तक जमा कर सकते हैं। पहले इसकी अधिकतम सीमा 4.5 लाख रूपये थी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की ब्याज दर भी 1 जनवरी 2023 से 8 प्रतिशत कर दी गई थी। सरकार अब महिला सम्मान बचत पत्र योजना भी शुरू करेगी, जिसके अन्तर्गत महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा।

आधारित संरचना विकास पर बल

सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव किया है। बजट में 2.4 लाख करोड़ रूपये रेलवे को आवंटित किए हैं। इन निवेश प्रस्तावों से विकास दर को गति मिलेगी, रोजगार सृजित होगा और भावी विकास हेतु सुदृढ़ आधार बनेगा।

बजट आकार विस्तार

वर्ष 2023–24 का में बजट व्यय की राशि 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राशि प्रस्तावित है। चुनाव पूर्व वर्ष के बजट में भी केन्द्रीय बजट में सरकार 'रेवडी कल्चर' दूर रह कर इन्फ्रास्ट्रक्चर व टिकाऊ विकास पर बल दिये हुए है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में आर्थिकी की मूलभूत कारकों पर जैसे कृषि, आवास, स्वास्थ्य, अधोसंरचना लोक कल्याण, कौशल विकास पर अधिक ध्यान दिया है।

प्रमुख क्षेत्रों को बजट आवंटन

विविध प्रमुख विभागों को बजट आवंटन अग्रानुसार है–

- 2.40 लाख करोड़ रू. रेलव मंत्रालय
- 1.96 लाख करोड़ रू. गृह मंत्रालय
- 1.12 लाख करोड़ रू. शिक्षा मंत्रालय
- 946 करोड़ रू. सी.बी.आई.
- 700 करोड़ रू. से अधिक खेल मंत्रालय
- 5.84 लाख करोड़ रू. रक्षा मंत्रालय
- 3,114 करोड़ रू. उड्डयन मंत्रालय
- 1,900 करोड़ रू. ई.वी.एम.
- 1564 करोड़ रू. जगगणना 2021

सकल बजट अनुमानः बजट 2023–24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपये और 45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान। 2023–24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रूपये होने का अनुमान है। ❑❑

बजट से मिला बैंकिंग कारोबार को बूस्टर डोज

बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए समीचीन कदमों का असर दिखने लगा है। बैंकों के मुनाफे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वहीं बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार की खबरें चहुंओर हैं। सकल एनपीए अनुपात भी घटकर 7 साल के सबसे निचले स्तर 5 प्रतिशत पर आ गया है और सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात के 5 प्रतिशत से भी कम रहने का अनुमान लगाया गया है। देश के सबसे बड़े कर्जदाता बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा है कि उसकी कुल आय तीसरी तिमाही में 98084 करोड रुपए रही जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में मात्र 78351 करोड़ रुपए थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की आय में भी 74.6 प्रतिशत का उछाल आया है तथा फंसे हुए कर्ज की स्थिति में सुधार हुआ है।

मालूम हो कि बैंकों की रीति नीति सुधारने के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव का जिक्र वित्त वर्ष 2023–24 के बजट में भी किया गया है। सरकार ने पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर अवसंरचना को मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2023 24 में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। यह राशि जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के बराबर होता है। इस राशि को मोटे तौर पर रेलवे, राजमार्ग और राज्यों की अवसंरचना को मजबूत करने में खर्च किया जाएगा, जिससे वैश्विक अवरोधों के बावजूद वृद्धि की रफ्तार को कायम रखने में मदद मिलेगी। पूंजीगत खर्च में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और बैंक ऋण की रफ्तार में तेजी आएगी। क्योंकि इससे बहुत सारे उत्पादों की मांग में तेजी आएगी, लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी और नए नए रोजगार का सृजन भी होगा। इन सभी गतिविधियों से बैंकों के कारोबार को प्रगति के पंख लग जाएंगे।

बजट में विभिन्न राज्यों में 30 कौशल विकास अंतरराष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के वर्जन 4.0 के तहत युवाओं को कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, एआईओटीटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल

आर्थिक समीक्षा के अनुसार घटता एनपीए अनुपात, कारपोरेट क्षेत्र के मजबूत बुनियादी आधार के कारण बढ़ती ऋण ब्याज दरों के बावजूद कारोबार में निवेश बढ़ाने के लिए ऋण की मांग और बैंक ऋण का प्रवाह अब धीरे–धीरे बढ़ रहा है।

– अनिल तिवारी

आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके तहत आगामी 3 सालों में 47 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष तौर पर नकदी हस्तांतरण के रूप में भत्ता दिया जाएगा ताकि उन्हें प्रशिक्षण लेने में किसी तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। प्रशिक्षण के बाद 47 लाख युवा खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अन्य ऋण योजनाओं के जरिए बैंक उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकते हैं।

बैंकिंग आंकड़ों के मुताबिक बार–बार रेपो रेट बढ़ने के बावजूद बैंकों के ऋण वितरण में तेजी बरकरार है। सभी क्षेत्रों में ऋण वृद्धि देखी जा रही है। खासकर गैर खाद्य बैंक ऋण में सालाना वृद्धि बढ़कर 15.3 प्रतिशत तक पहुंच गई है। हालांकि ऋण वृद्धि की रफ्तार अधिक होने के कारण बैंकों पर पूंजी जुटाने का दबाव बढ़ गया है। 15 जनवरी 2023 तक ऋण वृद्धि सालाना आधार पर 16.6 प्रतिशत थी, जबकि जमा वृद्धि 10.7 प्रतिशत ही रही। आर्थिक समीक्षा के अनुसार घटता एनपीए अनुपात, कारपोरेट क्षेत्र के मजबूत बुनियादी आधार के कारण बढ़ती ऋण ब्याज दरों के बावजूद कारोबार में निवेश बढ़ाने के लिए ऋण की मांग और बैंक ऋण का प्रवाह अब धीरे–धीरे बढ़ रहा है।

प्रस्तुत बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए नई कर्ज गारंटी योजना शुरु होनी है, जिसके तहत देश में मौजूद 84 हजार से अधिक स्टार्टअप के लिए 1 अप्रैल 2023 एमएसएमई को दो लाख करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाना है। पूर्व में इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम योजना से एमएसएमई क्षेत्र को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। देश में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाइयां है, जिनमें 13 करोड़ से अधिक लोग काम करते हैं। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र का देश की जीडीपी में लगभग 35 प्रतिशत का योगदान होता है।

हालिया ऋण वृद्धि की गति में तेजी मुख्य तौर पर छोटे ऋणों और आवास ऋणों में आई तेजी के कारण संभव हो सकी है। आवासीय मांग बढ़ने से निवेश में आगे और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन लगभग 70 प्रतिशत बढ़ाते हुए 79000 करोड रुपए से अधिक का कर दिया गया है। इस गुणात्मक वृद्धि से बैंकों के कारोबार में निश्चित रूप से इजाफा होगा और बैंकों की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

इसी तरह कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण की मांग को सरकार के रियायती संस्थागत कर्ज से मदद मिलेगी। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 20 लाख करोड़ों रुपए ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले बजट में यह लक्ष्य 18.52 लाख करोड़ ही था। कृषि क्षेत्र के लिए अलग से एक कोष बनाने की बात कही गई है क्योंकि करोना काल और उसके बाद भी कृषि क्षेत्र ने विकास की गति को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खेती को डिजिटल बनाने, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सहकारी समितियों की गतिविधियों को आगे करने के लिए परंपरागत घोषणाओं के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में लगभग तीन करोड़ घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि मनरेगा के बजट में 33 प्रतिशत की कटौती की गई है, लेकिन मनरेगा के मद में कटौती के बावजूद कृषि से जुड़े बजट प्रावधानों के कारण बैंकिंग कारोबार में वृद्धि होने का अनुमान प्रमुख औद्योगिक संगठनों ने लगाया है।

परंपरागत हस्तशिल्प कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के जरिए वित्तीय समर्थन की बात कही गई है। इसके तहत उत्पादन बढ़ाने और विपणन की गति में तेजी लाने की भी बात प्रमुखता से कही गई है। मछली पालन के लिए 6 हजार करोड़ रुपए की रियायती ऋण योजना शुरू की जाएगी, जिससे ऋण की मांग में वृद्धि होगी और यह सब काम बैंकों की आर्थिक रफ्तार को तेज करेगा।

वर्तमान मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2023 24 मई 11 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान को इससे भी बल मिलता है कि राजकोषीय घाटा 6.4 प्रतिशत से घटाकर अगले साल 5.9 प्रतिशत पर लाने की बात बजट में प्रमुखता से कही गई है। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए गैर कर राजस्व में वृद्धि से सरकार को राहत मिली है। क्योंकि दूरसंचार और पेट्रोलियम क्षेत्र से इस समय सरकार को अच्छी कमाई हो रही है। वही, विनिवेश से भी 51हजार करोड रूपए जुटाने का अनुमान किया गया है। ध्यान रहे कुल बजट व्यय के एक रुपये में 34 पैसे उधार लेने का लक्ष्य तय किया गया है। फिलहाल आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए उधारी लेने की जरूरत है, इसलिए उधारी को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। देश में बैंकिंग कारोबार को रफ्तार मिलना आवश्यक है। मौजूदा बजट से इस रफ्तार को पंख लग सकते हैं जिससे विकास को भी बल मिलेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले और अधिक मजबूती से खड़ी रहेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि कड़े और बड़े राजकोषीय संतुलन की हिमायती केंद्र की सरकार ने रोजगार और नौकरिया पैदा करने के उद्देश्य से प्रमुख क्षेत्रों में जो पूंजीगत खर्च का आंकड़ा बढ़ाया है उसका माकूल इस्तेमाल होता है तो विभिन्न मोर्चो पर कामयाबी मिलेगी बैंकों के कारोबार भी अबाध गति से चलते रहेंगे। ❑❑

अमृत बेला का स्वदेशी बजट

माननीया वित्त मंत्री द्वारा 2023–24 साल का जो बजट भारतीय संसद में 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया, वह स्वदेशी चिंतन और स्वावलम्बन के सिद्धांतों पर आधारित है। सरकार समझ चुकी है कि स्वरोज़गार और उद्यमिता तथा कौशल विकास दीर्घगामी आर्थिक विकास के लिये अपरिहार्य हैं। सरकार ने सहकारिता, विकेंद्रित व्यवस्था तथा पर्यावरण के विषय को वरीयता दी है। प्राकृतिक खेती और जैविक खाद के उपयोग को बढ़ाने के साथ–साथ गोवर्धन योजना के तहत 500 नये अवशिष्ट से सम्पदा संयंत्रों द्वारा काम में लिये जाना तथा तटीय क्षेत्रों में मेंगरोव–पौधाकरण योजना पर्यावरण के बढ़ते हुए ख़तरों से हमारी रक्षा करेगी। स्थानीय वस्तुओं विशेषकर ग्रामोद्योग तथा लघु–उद्योग को प्रोत्साहन तथा उनके लिये उचित विपणन एवं ऋण की व्यवस्था के लिये आवश्यक नीति निर्देश दिये हैं। बिना किसी संपत्ति के गिरवी रखे सरकारी गारंटी पर ऋण से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएँगे जिन पर 1 प्रतिशत ब्याज में भी छूट दी जायेगी। सरकार ने इसके लिये 900 करोड़ रुपये का एक कोरपस फंड बनाया है ताकि किसी बैंक के संभावित नुकसान की भरपाई की जा सके। हमारे देश में 6.3 करोड़ से अधिक लघु उद्योग हैं जो सकल घरेलू उत्पाद का 31 प्रतिशत और हमारे निर्यात का 45 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करता है तथा लगभग 12 करोड़ लोगों को रोज़गार देता है। यानि कृषि और लघु उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के बुनियाद हैं और इस बजट में इन दोनों क्षेत्रों के विकास का और उनकी समस्याओं को सुलझाने का भरसक प्रयास किया गया है।

युवाओं और महिलाओं के सर्वांगीण विकास तथा उनकी ऊर्जा का राष्ट्र–निर्माण में योगदान को स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के द्वारा पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है और इसलिये इस योजना के तहत उनके उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा उचित मूल्य पर उनके विपणन की व्यवस्था पर ज़ोर दिया गया है।

प्राकृतिक खेती और जैविक खाद के उपयोग को बढ़ाने के साथ–साथ गोवर्धन योजना के तहत 500 नये अवशिष्ट से सम्पदा संयंत्रों द्वारा काम में लिये जाना तथा तटीय क्षेत्रों में मेंगरोव–पौधाकरण योजना पर्यावरण के बढ़ते हुए ख़तरों से हमारी रक्षा करेगी।

– डॉ. धनपतराम अग्रवाल

रुस-यूक्रेन युद्ध तथा अन्य भौगोलिक-राजनैतिक कारण अनिश्चितता के कारण अभी भी बने हुए हैं। भारत जी-20 देशों का नेतृत्व कर रहा है और आशानुकूल विश्व अर्थव्यवस्था के वर्तमान ख़ामियों को दूर कर एक लोकतांत्रिक और बंधुत्व पर आधारित परस्पर सहयोग के द्वारा विकास की नई अवधारणा बनेगी, इसका हम सभी को विश्वास है।

कृषि तथा मत्स्य एवं पशुपालन पर आधारित जीविका में सुधार के लिये आवश्यक निर्णय भी लिये हैं। मत्स्य संपदा की योजना के तहत छोटे मछुवारों के लिये 6000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। देश के छोटे किसानों को नगद आर्थिक मदद से लगभग 11.4 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं और 2.2 लाख करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक में जमा कराये जाने से बिचौलियों द्वारा उनको वंचित करने का रास्ता बंद हो गया है। 47.8 करोड़ जन–धन योजना में बैंक खाते खुल चुके हैं। सरकार ने जल जीवन योजना के तहत 9 करोड़ लोगों के घरों में पीने के पानी की व्यवस्था की है और 11.7 करोड़ शौचालयों की व्यवस्था की है जो ग्राम्य–जीवन के जीवन–स्तर को उत्तम बनाने में एकसराहनीय कदम है जो लगातार कई वर्षों से सरकार पालन कर रही है ताकि अंत्योदय तथासमावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ये कदम विकास के प्रयास में आर्थिक विषमता को भी दूर करने में सहायक होंगे। इन सब बातों के नतीजे आने वाले वर्षों में भारत को बेरोज़गारी और ग़रीबीमुक्त एक उन्नत एवं समृद्धशाली राष्ट्र बनाने में सहायक होंगे, ऐसी आशा है।

वर्तमान में महंगाई एक बड़ी समस्या है। कोविड महामारी तथा रुस–यूक्रेन युद्ध की वजह से सारा विश्व मंदी और महंगाई की चपेट में है। एक तरफ़ अमेरिका 40 साल की रिकार्ड–तोड़ महंगाई से जूझ रहा है तो चीन 40 साल की सबसे कम आर्थिक विकास की मंदी से परेशान है। यूरोप के अधिकांश देशों में मंदी और महंगाई दोनों से वहां की जनता परेशान है। ऐसी विषम तथा विशद परिस्थितियों में भारत महंगाई पर नियंत्रण रखते हुए विश्व की सबसे तेज रफ़्तार से 6.8 प्रतिशत की दर से आर्थिक उन्नति कर रहा है और आने वाले साल 2023–24 में भी आर्थिक विकास दर 6.5 के आसपास रहने की उम्मीद है। यह इस बात का संकेत है कि भारत की आर्थिक नीतियाँ एवं उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। 2011–12 की तुलना में जब कृषि क्षेत्र हमारी राष्ट्रीय आय का सिर्फ़ 16.6 प्रतिशत हिस्सा था वह 2021–22 में बढ़कर 20.19 प्रतिशत हो गया है। यह इस बात का द्योतक है कि हमारे किसानों की आय में इज़ाफ़ा हुआ है। 2014 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2022 में दोगुनी यानि 1.97 लाख हुई है यह भी आर्थिक विकास में सबका सहभागी होने का परिचायक है। पिछले 8–9 वर्षों में हमारा देश विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दसवें पायदान से उठकर पाँचवे स्थान पर पहुँचा है तो यह भी प्रत्येक भारतीय के लिये गर्व की बात है। अगले 25 वर्ष देश की आज़ादी के अमृत–काल के रूप में मनाये जा रहे हैं और 2047 में जब 15 अगस्त को लाल क़िले पर झंडा फहराया जायेगा, उस समय भारत सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान पर होगा, इस बात के संकेत हमें इस बजट में देखने को मिलते हैं। 10 लाख करोड़ के पूँजीगत खर्च का आवंटन जो कि पिछले वर्ष के 7.5 लाख करोड़ की तुलना में 33.33 प्रतिशत ज़्यादा है। रेल के भी पूँजीगत खर्च के लिये 2.4 लाख करोड़ का प्रावधान है। किसान ऋण 20 लाख करोड़ का होगा, ग़रीबों के लिये मुफ़्त में अनाज वितरण की व्यवस्था जो कोविड कल में चालू कीगई थी और उसे लगभग ढाई वर्ष चलाने के बाद अगले एक वर्ष तक चलाने के लिये 2 लाख करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री आवास–योजना के लिये भी बजट में 79000 करोड़ रुपये आवंटित 66 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है जो कि समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने में मददगार सिद्ध होगा। यह भी उस परिस्थिति में जब कि आर्थिक घाटे की दर में पिछले वर्ष 6.4 प्रतिशत की तुलना में 5.9 की गिरावट के साथ विकास दर को 6.5 पर रखने की योजना बनाई गई है। यहाँ इस बात को समझ लेना उपयुक्त होगा की विश्व–स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में अगर अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है और यह क़ीमत 100 डालर प्रति बेरल तक होने की अवस्था में विकास दर में कुछ परिवर्तन हो सकता है। रुस–यूक्रेन युद्ध तथा अन्य भौगोलिक–राजनैतिक कारण अनिश्चितता के कारण अभी भी बने हुए हैं। भारत जी–20 देशों का नेतृत्व कर रहा है और आशानुकूल विश्व अर्थव्यवस्था के वर्तमान ख़ामियों को दूर कर एक लोकतांत्रिक और बंधुत्व पर आधारित परस्पर सहयोग के द्वारा विकास की नई अवधारणा बनेगी, इसका हम सभी को विश्वास है। ❑❑

बजट में सबके सपनों का सम्मान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद से कहीं अधिक अच्छा बजट पेश किया है। जिनको भी यह आशंका थी कि देश अन्य बड़े देशों की तरह मंदी के दौर में प्रवेश कर रहा है और सरकार भी आर्थिक दुष्चक्र में फंस रही है, उन्हें घोर निराशा मिली है और जिनको यह भरोसा था कि वैश्विक स्तर पर भारत अकेला देश होने वाला है, जो न सिर्फ कोविड और युद्ध के प्रभाव से खुद को निकाल लेगा, बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हो जाएगा, उसके लिए यह बजट सोने में सुहागा है। उद्योग जगत इतना गदगद है कि वह इस बजट को 10 में से 20 नंबर देने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण के आने के बाद कहा था कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पूरा प्रयास करेंगी कि यह बजट आंकाक्षाओं और अपेक्षाओं का बजट होने के साथ एक ग्लोबल सितारा के रूप में देश को आगे बढ़ाने वाला बजट पेश करें। और ऐसा ही हुआ। वित्त मंत्री ने इस बजट में भरपूर पैसा, लगभग सभी क्षेत्रों में नई टैक्नोलॉजी का रोड मैप और भविष्य को संवारने वा ला मार्ग दर्शन भी प्रस्तुत किया। 10 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय का बजट, 22 लाख करोड़ रुपये का कृषि लोन, 7900 करोड़ रुपया की आवास योजना, दो लाख 40 हजार करोड़ रुपये रेलवे के लिए और हजारों करोड़ रुपये की सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बजट की गारंटी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के भविष्य को संवारने वाले कई प्रयोजनों की घोषणा की है, जिससे आने वाले साल में भारत की तस्वीर बदल सकती है।

आठ साल में भारत की तस्वीर वैसे काफी बदल गई है। जब से नरेन्द्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है, भारत में प्रति व्यक्ति की आय बढ़कर दोगुनी हो गई है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में यह बताया कि इस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय एक लाख 97 हजार रुपये है जो कि अब तक का सबसे अधिक है।

– विक्रम उपाध्याय

आठ साल में भारत की तस्वीर वैसे काफी बदल गई है। जब से नरेन्द्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है, भारत में प्रति व्यक्ति की आय बढ़कर दोगुनी हो गई है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में यह बताया कि इस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय एक लाख 97 हजार रुपये है जो कि अब तक का सबसे अधिक है। आज भारत में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। मुफ्त खाद्यान्न योजना कोविड के दौरान प्रारंभ की गई थी वह आगे एक साल के लिए और बढ़ा दी गई है और उसके लिए बजट में दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया

है। आम गरीब का जीवन सरल और सुविधायुक्त रहे, इसका प्रयास लगातार आठ साल से यह सरकार करती आ रही है और इस प्रयास का परिणाम भी सामने है। मोदी सरकार ने इस दौरान 11 करोड़ 70 लाख घरों में शौचालय का निर्माण किया है, नौ करोड़ घरों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया है, वैक्सीन की 220 करोड़ डोज मुफ्त उपलब्ध कराई गई है। पीएम जनधन स्कीम के तहत 47 करोड़ 80 लाख लोगों के खाते खुलवाए गए हैं और दो लाख 20 हजार करोड़ रुपये पीएम किसान निधि योजना के तहत देश के किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया है।

यह देश किसानों का है, उनकी आय बढ़े बिना वास्तविक तरक्की नहीं हो सकती। इस बार के बजट में मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए भरपूर वित्त की व्यवस्था के साथ ही उसे टेक्नोलॉजी और अनुसंधान से सीधे जोड़ दिया है। 22 लाख रुपये के कृषि लोन के प्रावधान के साथ साथ छह हजार करोड़ रुपये का अलग प्रावधान मछुआरों के लिए भी किया गया है। खेती एक विरासत है और इस विरासत को बचाने के लिए इस बजट में गजब का प्रावधान किया गया है। सरकार इस साल एक करोड़ किसानों को रासायनिक खादों के बिना एवं पूरी तरह जैविक खेती के लिए चुनेगी और उन्हें विशेष प्रोत्साहन देगी ताकि हमारी परंपरागत खेती बची रहे और रसायनिक खादों व कीटनाशकों के आयात को भी कम किया जा सके।

स्टार्टअप्स के मामले में भारत विश्व में ती सरा सबसे अधिक स्टार्टअप्स वाला देश है। प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप इस बजट में कृषि क्षेत्र में लिए स्टार्टअप्स की भूमिका बड़ी कर दी गई है। ये स्टार्टअप्स किसानों को यह जानकारी देंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल लगाएं। देखभाल कैसे करें। इनकी उत्पादकता कैसे बढ़ाएं और इन्हें कहां और कैसे बेचे। इसी क्रम में सरकार ने सहकारी संस्थाओं को भी इस बजट के जरिए नई जिम्मेदारी है। सहकारी संस्थाएं कृषि उपजों के उचित भंडारण के लिए ढांचागत व्यवस्था का निर्माण करेंगी ताकि किसान उचित समय में अपनी उपज को बाजार में बेचकर अधिकतम मुनाफा कमा सके।

कृषि के साथ सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और कोरोना के बाद इन पर ही सबसे अधिक मार पड़ी है। सरकार ने आज इनके लिए कई बजटीय प्रावधानों की घोषणा की है। एक तो कोविड के दौरान परियोजनाओं को पूरा नहीं करने के कारण जिन एसएमई इकाइयों की धरोहर राशि या प्रोफारमेंस गारंटी के रूप में काटी गई राशि को जब्त कर ली गई थी, वे अब सब लौटाई जाएंगी। दूसरा दो लाख करोड़ रुपये का लोन फंड सृजित किया गया है और क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बिना किसी कोलेटरल के लोन के लिए भी 9 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एसएमई इकाइयों को सरकार केवल एक प्रतिशत ब्याज पर यह लोन जारी करेगी।

इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा पूंजीगत खर्च की राशि में बढ़ोतरी करना है। सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस साल 33 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिपें चर यानी पूंजीगत व्यय की घोषणा की है। पूंजीगत व्यय का आशय ऐसे खर्च से है, जिससे सराकर देश के लिए संपत्ति का निर्माण करती है। यह मुख्यतौर पर ढांचागत विकास, मशीनरी और कार्यशील पूंजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका आशय है कि सरकार 10 लाख करोड़ रुपये सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे और अन्य ट्रां सपोर्ट मोड पर खर्च करेगी। इससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होगा, क्योंकि ढांचागत क्षेत्र में व्यय का मतलब, सीमेंट, स्टील, ट्रां सपोर्ट और अन्य सहयोगी उद्योगों में भी विकास होना है।

रही बात कर और शुल्क के ढांचे में परिवर्तन की, तो इस बजट में जहां उद्योगों के लिए राहत दी गई है। वही आम और सैलरी क्लॉस के लोगों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया गया है। भारत पूरी दुनिया के लिए एक मैन्यूफैक्चरिंग हब बने इसके लिए आयात शुल्कों में कुछ छूट के ऐलान किए गए हैं, खासकर मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी कच्चे माल के आयात को आसान बना दिया गया है। बहुत दिनों से यह कहा जा रहा था कि मध्य आयवर्ग के लिए यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि यह वर्ग ही देश के उपभोक्ता बाजार को संभालता है। इस बजट में सारी शिकायतें दूर कर दी गई हैं। टैक्स डिडक्शन की सीमा तीन लाख करने के साथ ही अब सात लाख की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। टैक्स स्लैब भी ऐसा बना दिया गया है कि अधिकतर करदाताओं को इसका लाभ मिल सकता है। तीन लाख तक निल और तीन से छह लाख तक केवल पांच प्रतिशत कर की दर रखी गई है। अब 15 लाख से अधिक आय वालों को ही 30 प्रतिशत का कर देना है।

कुल मिलाकर इसे भविष्यपरक बजट कहा जा रहा है। यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ भारत दुनिया का सबसे अधिक तेजी से बढ़ रही अर्थव्यस्था बना रहेगा, बल्कि पांच ट्रिलियन की इकोनोमी बनने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा और जर्मनी एवं जापान को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ❑❑

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2023/2/1/Vikram-Upadhyay-s-article-on-budget.php

अमृतकाल का पहला बजट

एक फरवरी को 2023–34 के लिए संसद में बजट पेश हुआ। भाजपा जब से सत्ता में आयी है बजट में भविष्य की बाते ज्यादा होने लगी है। इस बार के बजट के बारे में भी यही कहा जा सकता है। भविष्य में बहुत कुछ करने की बाते सुनने को अच्छी लगती है लेकिन यह भी सही है की भविष्य की बातों का इंतजार करना पड़ता है। भविष्य की बातों में आज की बात ढूँढना भी एक कठिन काम होता है। इसलिए बजट में सरकार आज के लिए क्या कर रही है यह भी महत्व का माना जाना चहिए।

सप्तर्षि का मार्गदर्शन

भाषण की शुरुआत में ही वित्तमंत्री ने बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा और इस काल के मार्गदर्शक तत्वों को सप्तर्षि कह दिया। आजकल के विकास साधने वाले जो मार्गदर्शक तत्व रहेंगे वह है – समावेशी विकास, अंत्योदय, अवसंरचना में निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र का विकास। निश्चित ही यह मार्गदर्शक तत्व के बारे में किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर नीतियों का आधार अच्छा है तो विकास होगा ही। लेकिन बजेट में ऐसा क्या है जो अर्थव्यवस्था को विकास की ओर ले जाएगा यह भी देखना जरूरी है।

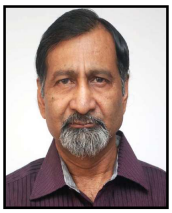

भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस लौट रही है और दुनिया के मुक़ाबले में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सप्तर्षि में अपेक्षित सभी ध्येय महत्व के है। इस सरकार की अब तक की योजनाएँ सफल होती दिख रही है इसलिए नए बजट में कही बातों पर काम होगा और अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त होगा ऐसा कहा जा सकता है।

– अनिल जवलेकर

सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ

पहली बार सरकार ने जेल में पड़े हुए गरीबों के बारे में विचार किया है और उनके बेल वगैरेह के लिए वित्तीय सहायता देने की बात की है। वैसे ही सरकार 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय और अग्रक्रम में शामिल परिवारों को एक साल के लिए अनाज मुफ्त देगी जिसका खर्चा केंद्र सरकार करेगी। पर्यटन बढ़ाने के जो प्रयास बजट में किए है उसमें रास्ते पर व्यवसाय करने वालों को लाभ हो सकता है। साथ ही गरीब वर्ग को सब्सिडी दी जाती है वह मिलती रहेगी जिसमे मुख्यता, कम कीमत में अनाज मिलना, एलपीजी के लिए मिलने वाली सब्सिडी वगैरह शामिल है।

इस बार वितमंत्री ने कर दाताओं के लिए निश्चित ही कुछ किया है। कस्टम डयूटी के स्लैब 21 से 13 किए है। आयात किए जाने वाली कुछ वस्तु पर की डयूटी कम की है। इससे भारत में बनने वाले मोबाइल फोन में लगने वाले पार्ट, लैब में बनने वाले डायमंड के सीड्स इत्यादि है। वैसे कुछ की डयूटी बढ़ाई है जैसे की सिल्वर बार, कम्पौंडेड रबर वगैरह। प्रत्यक्ष करो में छोटे उद्योग एवं व्यवसाय करने वालों को कर अनुमानित आय की सीमा 2 करोड़ तथा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ तथा 75 लाख रुपए की है। सहकारी और चीनी उद्योग को भी राहत दी गई है। प्राथमिक सहकारी समिति जैसी समितियों के सदस्य अब 2 लाख रुपए तक नगद रूप में पैसे जमा करा सकते है। मकान में निवेश करनेवालों तथा बीमा पॉलिसी धारको को अब कैपिटल गेन में 10 करोड़ रुपए तक ही छूट मिलेगी।

आय कर की रेबेट रु 5 से 7 लाख की है। अब रु 3 लाख तक कोई कर नहीं होगा। रेट भी कम किए है। रु 3–3 लाख से स्लैब बढ़ेगा और रेट 5 प्रतिशत से बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड घटाव अब नई टैक्स प्रणाली में भी मिलेगा और यह अच्छा प्रस्ताव है। लीव एन्कैशमेंट की लिमिट भी रु 3 लाख से रु 25 लाख की है जो उपयुक्त सीध होगी। विशेष वरिष्ठ नागरिकों की पोस्ट डिपॉज़िट की सीमा रु 15 लाख से रु. 30 लाख की है यह भी अच्छा दिलासा होगा। महिला बचत योजना भी जाहीर की है जो जरूरी थी।

कृषि क्षेत्र

कृषि विभाग की लगभग सारी योजनाएँ पूर्ववत चालू रहेंगी। जैसे कि फसल बीमा योजना, इंटरेस्ट सबवेंशन योजना, किसान सन्मान योजना (इसमे कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई। रुपए 6000 प्रति वर्ष किसान परिवार को मिलते रहेंगे), किसान मानधन योजना (वृद्ध किसान को रु 3000 प्रति माह पेंशन), एफ़पीओ को बढ़ावा देने वाली योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वगैरह चालू रहेंगी। नई योजना की बजेट में जो घोषणा हुई है उनमें कृषि के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और कृषि वर्धक निधि स्थापन करना और भारत को 'श्री अन्न' (मिलेट) का ग्लोबल केंद्र बनाने की बात मुख्य है। इसका मतलब किसान को यह बजेट में अप्रत्यक्ष लाभ हुआ है। किसान सम्मान में बढ़ोत्तरी और फसल बीमा योजना में बदलाव की अपेक्षा थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर से निश्चित किसान को भविष्य में लाभ होगा और ग्रामीण विभाग में रोजगार भी बढ़ेंगे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा एक अच्छी बात

यह बजेट में इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात प्रमुखता से की है। ट्रांसपोर्ट सैक्टर पर ज़ोर साफ है। करीब 100 प्रोजेक्ट इसमे शामिल किए जाएंगे। 50 नए एयरपोर्ट, वॉटर एरोड्रम वगैरह निर्माण किए जाएंगे। शहरी विभाग का इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कर इस बजेट ने एक कदम आगे बढ़ाया है। अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड एक नया फंड होगा जो वरीयता ऋण देने में जो कमी आएगी उससे बनाया जाएगा और राज्य सरकार इसमे सहयोग करेगी। शहर–शहर में इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में यह निधि सहायक होगा ऐसी अपेक्षा है। इसमें भी महा पालिका और राज्य सरकारे कितनी दिलचस्पी दिखाते है यह देखने वाली बात होगी।

खर्चा ज्यादा आमदनी कम

वित मंत्री ने बहुत से बाते कही जिसमें शिक्षकों की ट्रेनिंग से लेकर सरकारी कर्मचारियों कि ट्रेनिंग तक की बाते शामिल है। नर्सिंग कोलेज खोलेने की बात और कई संशोधन करने की बात भी उन्होने की जो सराहनीय है। ई–कोर्ट की स्थापना करने की भी बात आगे चलकर उपयुक्त होगी। और भी बहुत सारी बाते वित्त मंत्री ने की, लेकिन सरकार की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है की जो सारे काम कर सके। सरकार के आय के हर रुपए में 34 पैसे उधार के है। 30 पैसे आय कर से और 17 पैसे जीएसटी से आते है। कस्टम ड्यूटी से सिर्फ 4 पैसे और यूनियन एक्साइज़ से 7 पैसे आते है। खर्चा देखा जाए तो 20 पैसे उधार का ब्याज देना पड़ता है। सब्सिडी पर 7 पैसे और डिफेंस पर 8 पैसे खर्च होते है। रु 45 लाख करोड़ के खर्चे में रु 35 लाख करोड़ राजस्व खाते में खर्च होंगे। 10 लाख करोड़ कैपिटल अकाउंट का है जिससे कुछ संपतिया बनेगी। करीब रु 18 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा है जिसमें राजस्व घाटा ही रु 8.70 लाख करोड़ है। निश्चित ही वित्त मंत्री चाहे घाटा घटने या घटाने की बात कर रही हो लेकिन महंगाई के बढ़ते माहौल में यह नुकसान करेगा इस में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

यह सही है कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल अच्छा नहीं है और सभी देश आत्म रक्षात्मक कदम उठा रहे है उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर हो रहा है। यह बात अच्छी है की भारत एक अकेला देश है जिसकी विकास की पैठ अच्छी है और सभी सकारात्मक घट रहा है। लेकिन इससे भारतीय व्यवस्था का खतरा कम नहीं हो जाता। इसलिए वित्तमंत्री जो करना चाहती है वैसा होगा ऐसा कहना मुश्किल है। यह जरूर है की भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस लौट रही है और दुनिया के मुक़ाबले में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सप्तर्षि में अपेक्षित सभी ध्येय महत्व के है। इस सरकार की अब तक की योजनाएँ सफल होती दिख रही है इसलिए नए बजट में कही बातों पर काम होगा और अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त होगा ऐसा कहा जा सकता है। ❑❑

बजट वर्ष 2023–24

'हर घर नल से जल' योजना का विस्तार

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने वर्ष 2023–24 के बजट में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 7192 करोड रुपए और जल जीवन मिशन के लिए 70 हजार करोड़ का बजट आवंटित किया है, वहीं देश की नदियों को जोड़ने की योजना के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है, जबकि अटल भूजल योजना के लिए 1000 करोड रुपए, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8587 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं।

बजट में किए गए प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि भारत अपनी आत्मनिर्भरता के बल पर आर्थिक विकास कर रहा है। सबको साफ और पर्याप्त जल के लिए जल जीवन मिशन को और गतिमान करने हेतु इस मिशन को इस वर्ष 70000 करोड रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इससे हमें 'घर–घर नल से जल' के संकल्प को पूरा करने में ओर अधिक गति मिलेगी। इस क्रम में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए हुए आवंटन से संपूर्ण स्वच्छता की बुनियाद को और अधिक मजबूती मिलेगी। चूंकि मोदी सरकार स्वच्छता और विकास को समान रूप से देखती है, इसलिए आजादी के इस अमृत काल में भारत की समृद्धि में प्राकृतिक संसाधनों की अहम भूमिका है। सरकार द्वारा देश की नदियों को जोड़ने की योजना के लिए 3500 करोड़ रू. का प्रावधान आने वाले समय में देश की उन्नति के लिए निर्णायक होगा। बजट में सोच विचार कर किए गए प्रावधान से भी यह लगता है कि जल समानता से सुरक्षित, संरक्षित और वितरित होगा। इसी संकल्प के लिए अटल भूजल योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8587 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में जब जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी। इसके पहले तक इस मद में मात्र 11139 करोड रुपए का प्रावधान तय किया गया था। वर्ष 23–24 के आम बजट में इसे बढ़ाकर 70 हजार करोड़ कर दिया गया है। जल जीवन मिशन सिर्फ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ही नहीं है, अपितु एक ईमानदार संकल्प है।

बजट में किए गए प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि भारत अपनी आत्मनिर्भरता के बल पर आर्थिक विकास कर रहा है। सबको साफ और पर्याप्त जल के लिए जल जीवन मिशन को और गतिमान करने हेतु इस वर्ष 70000 करोड रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

कोरोना महामारी ने हमें सिखाया कि इस वायरस के डर से उबरने के लिए साफ और पर्याप्त पानी की कितनी जरूरत है। पानी पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ–साथ आर्थिक विकास भी निर्भर है। इस समय देश में कुल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध है, जिसमें 609 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल और शेष भूजल है। जलाशयों की भंडारण क्षमता सीमित है। इसके साथ ही हमारे देश में पानी की एक स्थानीय भिन्नता है यानि अर्ध शुष्क क्षेत्र को मानसून में कम मात्रा में पानी मिलता है, तो पूर्वी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र को अधिक। साल के लगभग 4 महीनों ही मानसून का पानी मिल पाता है।एक आंकड़ा यह भी है कि वर्ष 2050 तक पानी की मांग इसकी आपूर्ति से अधिक हो जाएगी। इस अतिरिक्त आपूर्ति के लिए पानी कहां से आएगा? पानी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्रों में मुख्य रूप से किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों द्वारा इसके उपयोग के दौरान पानी को बचाने की आवश्यकता है।पानी का संरक्षण सिर्फ वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है। अगस्त 2019 में लगभग 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन (55 लीटर पानी प्रति कर प्रतिदिन) देने के लिए

प्रधानमंत्री की पहल पर हर घर जल कार्यक्रम शुरू किया गया था।केंद्र सरकार के वर्ष 2021 22 के वित्तीय बजट में शहरी क्षेत्र में भी पानी की पहुंच की परिकल्पना की गई थी। यह माना गया था कि मेक इन इंडिया के लिए पानी की उपलब्धता आवश्यक होगी। यह पानी कहां से आएगा? हमें पानी बचाने और बढ़ी हुई पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए संरक्षण की आवश्यकता है।

बजट के प्रावधानों पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई। सरकार की ओर से राज्यसभा में 8 करोड़ तथा लोकसभा में 11 करोड़ घरों तक पहुंचाने का दावा किया गया है। हालांकि आंकड़ों की यह गड़बड़ी मानवीय भूल भी हो सकती है लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2019 में शुरू किया गया जल जीवन मिशन आखिर कहां तक पहुंचा है? अक्टूबर 2019 तक देश में हर किसी के लिए शौचालय की व्यवस्था कर देना सरकार की एक बड़ी सफलता थी। ऐसे में इसके बाद हर घर तक साफ पानी पहुंचाना ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा वादा है, जिसकी सख्त जरूरत भी है। ऐसे में इस मिशन के लिए आवंटन भी साल दर साल लगातार बढ़ता गया।बजट आवंटन के बढ़ने से एक अर्थ यह भी निकलता है कि भारत में घरेलू पेयजल की सतत आपूर्ति अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। भारत हमेशा से लीकेज की समस्या से ग्रस्त रहा है जिसका मतलब है कि जिन गांवों और बस्तियों तक सुरक्षित पेयजल की सुविधा पहुंच चुकी थी वह विभिन्न कारणों के चलते फिर से फिसल कर नॉट कवर्ड में आ जाते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है जिसमें पानी के स्रोतों का सुख जाना और सुविधाओं का रखरखाव ना करना भी शामिल है। वर्ष 2013 से 2019 के बीच ग्रामीण जलापूर्ति की स्थिति का विश्लेषण करने वाली कैग रिपोर्ट से पता चलता है कि इस अवधि में लगभग 5 लाख बस्तियां पूर्ण रूप से कवर की कोटि से आंशिक रूप से कवर की श्रेणी में चली गई है। ऐसी बस्तियों की संख्या आंध्र प्रदेश बिहार कर्नाटक झारखंड उड़ीसा राजस्थान उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में अधिक हैं। ऐसे में देश के ग्रामीण घरों में नलों की संख्या बढ़ाने के बावजूद ग्रामीण जलापूर्ति की स्थिति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है।

ऐसे में हमें मुख्य रूप से चार स्तरों पर जल संरक्षण के लिए अहम प्रयास करने होंगे। पहला, चूकि जल संसाधन राज्य का विषय है इसलिए राज्यों की इकाइयों को सक्रिय होना होगा। जल संरक्षण और जल संचयन का प्रयास स्थानीय स्तर पर होना चाहिए क्योंकि स्थानीय प्रयासों के बिना जल संरक्षण के प्रयास व्यापक अभियान का रूप नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा, पानी की बचत और संरक्षण के लिए पानी के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को अपनाया जाना चाहिए। अगर हम दिल्ली को उदाहरण के रूप में देखें तो यहां प्रतिदिन 3420 मिलियन लीटर पानी की खपत होती है जिसमें मात्र 1600 मिनियन लीटर पानी का उपयोग होता है बाद बाकी सीवेज में चला जाता है। तीसरा जल संरक्षण को एक बड़ा अभियान बनाने के लिए विभिन्न भागीदारों की भागीदारी की आवश्यकता होगी। केंद्रीय अभियान पर्याप्त नहीं है, गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय लोगों और व्यक्तियों को स्थानीय पंचायतों के साथ गहनता से शामिल किए जाने पर विचार करना चाहिए। चौथा, जल प्रबंधन और जल संसाधन दोनों पर एक साथ ध्यान दिए जाने की जरूरत है। लोगों में यह भाव आना चाहिए कि पानी एक मूलभूत अधिकार है और इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना नैतिक जिम्मेदारी है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 8–9 वर्षों में सार्वजनिक सेवा, वितरण, सरकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक आदर्श बदलाव देखा गया है। पहले लगभग असंभव माने जाने वाले कठोर लक्ष्यों को अपनाना और उन्हें समय पर पूरा करना अब एक सामान्य बात हो गई है। सरकार के प्रयासों से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली है। अगस्त 2019 में जब जल जीवन मिशन का प्रारंभ किया गया था उस समय लगभग 3.2 करोड ग्रामीण परिवारों के पास नल से जल आपूर्ति की सुविधा थी। आज 11 करोड़ परिवारों को उनके घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो रही है यानी 3 वर्ष में लगभग 3 गुना से अधिक घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। यह एक अच्छी रफ्तार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और हर नल जल का लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ होगी। ❑❑

सबकी उम्मीदों पर खरा है बजट

तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव की चल रही प्रक्रिया के बीच वर्ष 2023–24 का आम बजट पेश हो चुका है। इस वर्ष अभी 6 और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगले साल वर्ष 2024 में लोकसभा का आम चुनाव भी होना है,इसलिए यह आम सोच थी कि बजट लोकलुभावन होगा। मध्यवर्ग को लेकर पहले से ही सकारात्मक संकेत देती आ रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सोच को बहुत हद तक सही साबित किया है। बजट का फोकस सरकारी खर्च बढ़ाकर आर्थिक विकास दर तेज करने पर है, लेकिन वित्त मंत्री की झोली से बच्चे जवान बूढ़े महिलाएं नौजवान किसान सबके लिए दिल खोल कर दिए जाने से यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार की नजर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है। "सबका साथ सबका विकास" के साथ–साथ सब को विश्वास में लेने का बजट है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। यह बहुत बड़ा फैसला है लेकिन इससे महंगाई दर बढ़ने का खतरा है। वित्त मंत्री ने वर्ष 24 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.9 प्रतिशत रखा है जो इससे पिछले साल में 6.4 प्रतिशत और उसके पिछले साल में 6.8 प्रतिशत था। कोरोना महामारी से उबरने के बाद यह एक तरह से ठीक कदम है। अभी आर्थिक रिकवरी को मजबूत बनाने की जरूरत है, इसलिए आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटे को धीरे–धीरे कम किया जा सकता है। सरकार ने पिछले साल के बजट में ही लक्ष्य रखा था कि वर्ष 2025 26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत तक ले आएंगे। कुल लगभग 45 लाख करोड़ के परिव्यय वाले भारी–भरकम बजट मैं 27.2 लाख करोड़ की आय कर संग्रह के जरिए होनी है, जबकि 15.4 लाख करोड रुपए सरकार उधार लेगी।

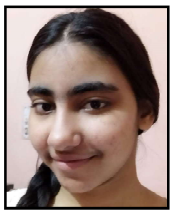

नए भारत के नजरिए से इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी दूरदर्शिता की नई लकीर खींचने की कोशिश दिखती है। आज दुनिया मेन्यूफैक्चरिंग में चीन का विकल्प तलाश रही है और बजट में हुए प्रावधानों से भरोसा मिलता है कि सरकार इस अवसर को भुनाने की रणनीति पर काफी आगे बढ़ चुकी है।

–वैदेही

मालूम हो कि देश में चल रहे आजादी के अमृत काल का यह पहला आम बजट है।यह बजट इसलिए भी खास है कि आजादी के बाद पहली बार महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्ताव तैयार किया है और महिला राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दी है। लाल चटख साड़ी में लाल रंग के बही खाते में बजट लेकर संसद में पहुंची वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर करदाताओं के चेहरे पर भी खुशी की लाली लाने की कोशिश की है।महिलाओं के विकास के लिए इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। बजट महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के लिए प्रेरित करता है। नये कर प्रावधानों के अनुसार नए 7 लाख रूपये सालाना आय अर्जित करने वाले को अब कोई कर नहीं देना होगा। वही पुराने कर ढांचे में तीन लाख तक की आय पर कोई कर नहीं होगा, पहले यह सीमा मात्र ढाई लाख रुपए तक की थी। इससे मध्यमवर्ग को राहत पहुंचेगी। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि सीमा को भी साढ़े चार लाख से बढ़ाकर 9 लाख रूपये कर दिया गया है। करोना काल में 28 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने, 14 करोड़ जनधन खाता खोले जाने, 10 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन देने, 12 करोड़ घरों में शौचालय बनवाने, सबको आवास का लक्ष्य हासिल करने तथा प्रति व्यक्ति आय 1. 97 लाख यानी लगभग 2 लाख रू. सालाना हो जाने का दावा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा बजट अगले 25 साल के विकास का ब्लूप्रिंट है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना की अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करने, महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत की घोषणा वित्त मंत्री ने की है या 2 साल के लिए होगा इसके तहत महिलाएं 2 लाख रू. जमा कर सकेंगी, जिस पर उन्हें 7.5 प्रतिशत

का ब्याज दिया जाएगा।

सरकार ने आधारभूत ढांचे के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन करते हुए हरित खेती हरित ऊर्जा तथा देश में मोटे अनाज को प्राथमिकता देने की बात कही है। किसानों की बेहतरी के लिए कृषि क्रेडिट कार्ड की सीमा 20 लाख करोड़ तक बढ़ा दी गई है। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के साथ–साथ देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है श्री अन्य योजना के लिए भारत ग्लोबल हब बनेगा। 47 लाख युवाओं को सीधे धन हस्तांतरण का ऐलान करते हुएवित्त मंत्री ने देश में 50 नए एयरपोर्ट बनवाने की घोषणा की।रेल के लिए 2.4 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। बजट में रेलवे को और अधिक स्मार्ट बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी इसके लिए 75000 करोड अलग से दिए जाएंगे। खेती में स्टार्टअप को बढ़ावा, डिजिटल ट्रेनिंग के साथ–साथ बागवानी के लिए 2220 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देश में कृत्रिम मेधा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में केंद्र खोले जाएंगे। कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं आरंभ की जाएंगी जीआईएफटी शहरों पर खास ध्यान तथा राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर भी बनाया जाएगा। छोटे उद्योगों को

गांव से शहरों की ओर बे–लगाम पलायन को देखें तो सरकार की इस पहल का दूरगामी महत्व समझ में आता है। बजट में स्वच्छ पेयजल, सफाई, पर्यावरण में सुधार, कनेक्टिविटी में सुधार, जैसे मदों के लिए अच्छा खासा प्रावधान किया गया है।

9000 करोड़ की क्रेडिट गारं टी के साथ–साथ केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।अदालती मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए ई कोर्ट के लिए 97000 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं।

नए भारत के नजरिए से इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी दूरदर्शिता की नई लकीर खींचने की कोशिश दिखती है आज दुनिया मेन्यूफैक्चरिंग में चीन का विकल्प तलाश रही है और बजट में हुए प्रावधानों से भरोसा मिलता है कि सरकार इस अवसर को भुनाने की रणनीति पर काफी आगे बढ़ चुकी है। घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात बिल को कम करने के लिए सरकार ने कई इंसेंटिव योजनाओं की घोषणा की है। छोटे और मझोले किस्म के उद्योगों को राहत इसके उदाहरण हैं। बजट के प्रावधानों से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार मनुफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत लॉजिस्टिक की लागत को कम रखने और घरेलू माल को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। एमएसएमई के बजट को बढ़ाने के पीछे भी यही महत्वाकांक्षा दिखती है। कृषि के बाद एमएसएमई रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है और करोना कि सबसे ज्यादा मार भी इन्हीं सेक्टरों पर पड़ी है। सरकार इन सेक्टरों को फिर से आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल योजना के मॉडल के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पैड अप कैपिटल की सीमा बढ़ाना इस सेक्टर को नई ताकत देने की मंशा दिखा रहा है।

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट में शहरों में गुणवत्तापूर्ण जीवन की जरूरत को भी पर्याप्त तरजीह दी है। गांव से शहरों की ओर बेलगाम पलायन को देखें तो सरकार की इस पहल का दूरगामी महत्व समझ में आता है। बजट में स्वच्छ पेयजल, सफाई ,पर्यावरण में सुधार, कनेक्टिविटी में सुधार, जैसे मदो के लिए अच्छा खासा प्रावधान किया गया है।

बहरहाल बजट को समग्रता से देखने पर पता चलता है कि सरकार पूंजीगत व्यय के जरिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश में खड़े रोजगार संकट को हल करने, दिन दिन चढ़ती महंगाई पर काबू करने से कहीं अधिक सरकार का ध्यान आसन्न चुनाव पर भी है। अब इसे अलग–अलग कसौटी पर कसा जा रहा है। सियासी जमात इसमें अपनी गुंजाइश और बाजार अपना भविष्य तलाश रहा है। ❑❑

भारत के अमृत काल का प्रथम बजट

विकसित राष्ट्र की आधारशिला रखने वाला बजट

भारत का अमृत काल प्रारम्भ हो चुका है और वर्ष 2047 में भारत अपनी स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा। उस समय तक भारत को विश्व के मानचित्र पर एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की प्रेरणा देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारतीय नागरिकों को दी है। अतः देश के पास अब केवल लगभग 24 वर्ष का समय ही शेष है, ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए प्रस्तुत किया गया केंद्र सरकार का बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की राह दिखा रहा है। यह बजट दरअसल अमृत काल का प्रथम बजट होने के कारण इसे भारत में अमृत काल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट भी कहा जा सकता है।

भारत में आध्यात्मिक दृष्टि से ऋषियों, मुनियों एवं गुरुओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर सफलता हासिल करने के कई उदाहरण सुनाई देते रहे हैं। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023–24 के केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदया ने बताया कि उन्होंने भी सप्तऋषियों के रूप में, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से, 7 प्राथमिकताएं तय की हैं। भारत में प्रकृति को सदैव ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इस दृष्टि से प्रथम प्राथमिकता तो यही तय की गई है कि प्रकृति को कम से कम नुक्सान पहुंचाते हुए देश का आर्थिक विकास किया जाय। अतः "ग्रीन ग्रोथ" की प्राथमिकता तय की गई है। देश के युवाओं को देश की आर्थिक प्रगति में शामिल करने के उद्देश्य से "यूथ पावर" के रूप में दूसरी प्राथमिकता, देश की आर्थिक प्रगति को "इंक्लूसिव डेवलपमेंट" के रूप में हासिल करने के उद्देश्य से यह तीसरी प्राथमिकता, समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक आर्थिक प्रगति का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से "रीचिंग द लास्ट माइल" के रूप में चौथी प्राथमिकता, रोजगार के अधिक से अधिक नए अवसर निर्मित करने के उद्देश्य से "इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट" के रूप में पांचवीं प्राथमिकता, देश में पूर्व से ही उपस्थित अंतर्निहित शक्तियों (जिन्हें हम भूल गए हैं) का देश हित में उपयोग करने के उद्देश्य से "अनलीशिंग द पोटेंशियल" के रूप में छठी प्राथमिकता, एवं भारत के नागरिकों को डिजिटल प्लेटफोरम पर ले जाने के उद्देश्य से "लॉंच आफ डिजिटल प्लेटफोरम" के रूप में सांतवीं प्राथमिकता निर्धारित की गई है। अमृत काल के प्रारम्भ होने के साथ ही, उक्त प्राथमिकताओं के आधार पर, भारत में बहुत तेज गति से कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

भारत में अब नई तकनीकी को अपनाने के साथ ही हमारी सांस्कृतिक परम्परा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है ताकि भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित किया जा सके।

– प्रहलाद सबनानी

केंद्र सरकार ने भारत के आधारभूत ढांचे को विकसित अवस्था में ले जाने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। केंद्र सरकार के पूंजीगत निवेश की राशि में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे वित्तीय वर्ष 2022–23 के 7.50 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। इतनी भारी भरकम राशि यदि केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत ढांचे को विकसित करने के लिए खर्च की जा रही है तो इससे देश में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित होंगे एवं देश में उत्पादों की मांग में भारी वृद्धि होगी तथा अंततः निजी क्षेत्र की कम्पनियों को भी अपने पूंजीगत निवेश को गति देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देश की आर्थिक प्रगति को बल देने के लिए यह एक क्रांतिकारी उपाय कहा जा सकता है।

इसी प्रकार, भारत में आधारभूत संरचना को विकसित स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से रेल बजट के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2.40 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 में 1.40 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। इस

प्रकार इस मद पर अब नए वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग दुगनी राशि खर्च की जाएगी। रेल्वे को विकसित अवस्था में लाने के लिए 75,000 करोड़ रुपए की लागत की कई नई योजनाएं भी प्रारम्भ की जाएंगी। साथ ही, देश में हवाई यातायात को और अधिक आसान बनाने के उद्देश्य से 50 अतिरिक्त नए एयरपोर्ट, हेलीपेड, वॉटर एयरोड्रम आदि बनाए जाएंगे। साथ ही, क्षेत्रीय हवाई संबद्धता को भी और अधिक मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे।

वित्तीय वर्ष 2023–24 का बजट रक्षा क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी सौगात लेकर आया है। केंद्रीय बजट में वर्ष 2023–24 के लिए रक्षा क्षेत्र को कुल 5.94 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो कुल बजट की राशि का 8 प्रतिशत है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। बजट में आवंटित की गई इस राशि का उपयोग हथियारों की आत्मनिर्भर तकनीक और भारत में ही इन उत्पादों के निर्माण के कार्य पर किया जाएगा। इससे देश में ही रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होंगे। वैसे, अब तो रक्षा क्षेत्र में उत्पादित उपकरणों एवं हथियारों आदि का भारत निर्यात भी करने लगा है। रक्षा के क्षेत्र को और अधिक मजबूती प्रदान करने से देश से इन उत्पादों के निर्यात को भी गति मिलेगी।

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा रोजगार के करोड़ों अवसर निर्मित किया जा रहे हैं अतः इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लाई जा रही है। साथ ही, तीन करोड़ रुपये के टर्नओवर तक के सूक्ष्म उद्योग को करों में छूट दी जा रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अधिक बल देते हुए 3,400 सरकारी

कृषि का क्षेत्र तो केंद्र सरकार के लिए प्रारम्भ से ही प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है और किसानों की आय को दुगना किए जाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। आज भी देश की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी गावों में निवास करती है एवं अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। अतः वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में भी कृषि क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर लाने का फैसला किया गया है। इससे देश में नए नए उद्योगों को स्थापित करने में अब और अधिक आसानी होगी।

कृषि का क्षेत्र तो केंद्र सरकार के लिए प्रारम्भ से ही प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है और किसानों की आय को दुगना किए जाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। आज भी देश की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी गावों में निवास करती है एवं अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। अतः वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में भी कृषि क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि क्षेत्र का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में पशुपालन, डेयरी पालन और मत्यस्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं अन्य कृषि कार्यों के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए की योजना है। मत्स्य उपयोजना में 6,000 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। कृषि–स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। गोबरधन योजना के अंतर्गत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी एवं प्राकृतिक खेती के लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स स्थापित किए जाएंगे। युवा किसानों की सहायता के लिए एक विशेष फंड का निर्माण किए जाने की भी योजना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आबंटित की गई राशि को 66 प्रतिशत से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया है। इससे भारतीय नागरिकों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण कार्य को गति मिल सकेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत खर्च की जा रही राशि को भी केंद्र सरकार का पूंजीगत निवेश ही कहा जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के खर्च से देश में आस्तियों का निर्माण ही तो हो रहा है एवं रोजगार के लाखों नए अवसर भी निर्मित हो रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र को भी अतिरिक्त महत्व प्रदान करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के साथ–साथ मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में "मल्टी–डिसिप्लीनरी स्टडी" के लिए कोर्स मटेरियल की व्यवस्था भी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। 740 एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूलों के लिए अगले तीन वर्षों के दौरान 38,000 नए शिक्षकों एवं सहायक स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इस बजट में केंद्र सरकार द्वारा जनजातियों के लिए विशेष स्कूलों हेतु 15 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सिविल सेवकों और सरकारी कर्मचारियों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑनलाइन ट्रेनिंग योजना भी प्रारम्भ की जाएगी।

अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत में अब नई तकनीकी को अपनाने के साथ ही हमारी सांस्कृतिक परम्परा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है ताकि भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित किया जा सके। ❑❑

प्रहलाद सबनानी: सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर, म.प्र.

कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर है अभी

पिछले साल पांच राज्यों के चुनाव में अपमानजनक हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने पदयात्रा के माध्यम से खुद को फिर से मजबूत करने का प्रस्ताव रखा था ताकि आम आदमी के साथ टूटते रिश्ते को फिर से कायम किया जा सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 14 राज्यों के 75 जिलों का भ्रमण करते हुए 135 दिनों की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने हर जगह यह संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत का बीज बो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही इस चुनौती को बेअसर कर सकती है तथा मोहब्बत के साथ समाज के हर वर्ग को एक साथ जोड़ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पदयात्रा ने भीड़ को आकर्षित किया तथा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ उत्साहित भी किया। कांग्रेस पार्टी के इस अभियान से राहुल गांधी की छवि में भी बहुत हद तक सकारात्मकता ही है। प्रतिदिन 20 किलोमीटर पैदल चलना चलते हुए आम लोगों के गले लगना तथा उनसे मिलकर उनकी बातों को ध्यान से सुनना जैसी गतिविधियां लोगों को अच्छी लगी। सोशल मीडिया के सम्यक प्रयोग तथा बड़े स्तर पर यात्रा को जमीनी बनाने के कौशल को लेकर संगठन में भी चर्चा बड़ी है। पार्टी का कह सकते हैं कि पुनर्वास तो हुआ लेकिन पार्टी के नाते उठने वाले महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अभी भी आने बाकी है।

बीते 8 सालों में ज्यादातर आलोचकों यहां तक कि पार्टी के कट्टर समर्थकों ने भी इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के भविष्य को लेकर तमाम उम्मीदें तज दी थी। केवल चुनावी पराजय के वजह से नहीं बल्कि इसलिए भी कि जिस तरह खराब तैयारी के साथ लड़खड़ा ती हुई चुनावी राजनीति में कांग्रेसी उतरती है, गुटीय झगड़ों को काबू में नहीं कर पाती, शीर्ष नेतृत्व उनीदा रहता है और सबसे अहम की जनता की नब्ज सही नहीं पहचान पाती। कांग्रेस के कई शीर्ष नेता जिनमें राहुल के कुछ करीबी विश्वासपात्र भी थे पार्टी छोड़ कर चले गए। मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक चुनाव जीतकर भी पार्टी सत्ता गंवा बैठी। पंजाब दिल्ली और मेघालय जैसे राज्यों में उसे आम आदमी पार्टी और तृणमूल पार्टी के लिए जगह खाली करनी पड़ी।

हालांकि भारत जोड़ो यात्रा ने लगभग मरणासन्न कांग्रेस को नया मकसद दिया पर लोग अब भी इसे राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के चुनावी विकल्प के तौर पर नहीं देख रहे हैं। यहां तक कि एक राष्ट्रीय विपक्षी गठबंधन भी अभी दूर की कौड़ी ही लग रहा है। 14 राज्यों के 75 जिलों से गुजरते हुए लगभग 3500 किलोमीटर की पदयात्रा से राहुल गांधी की छवि में बेशक सुधार आया है लेकिन दिल्ली का तख्त ओ ताज अभी भी उनकी पहुंच से काफी दूर है।

– के.के. श्रीवास्तव

यात्रा ने पार्टी को उसकी संगठिनिक सुस्ती से झकझोरा है लेकिन लोगों को अब भी भरोसा नहीं है कि कांग्रेस के पास आखिरी अवरोध यानि चुनावी बलिवेदी को पार करने की कुब्बत है।

यात्रा से इस बात के भी कोई संकेत नहीं मिलते इस यात्रा का मंतव्य क्या था? क्योंकि इस यात्रा को चुनावी यात्रा के रूप में भी जोड़ कर किसी ने नहीं देखा क्योंकि चुनाव जीतने के लिए एक स्पष्ट चुनावी एजेंडा, केंद्रित नेतृत्व, समर्पित संगठन, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता और निश्चित रूप से पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर पार्टी इस यात्रा को इस एजेंडे पर सही साबित करने की कोशिश करती है तो उसमें संदेह होता है। वैसे भी सपना देखना और फिर उस सपने को मूर्त रूप देना दो अलग–अलग चीजें हैं। चुनावी हार जीत तो वैसे भी एक दूसरे तरह का खेल है।इसमें कोई संदेह नहीं कि 2019 में मोटे तौर पर 119 मिलियन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था लेकिन यह पर्याप्त नहीं है विशेष रूप से आप और तृणमूल कांग्रेस की नई चुनौतियों के सामने वास्तव में कांग्रेस मुक्त विपक्ष के बारे में दबी हुई बातें अभी हवा में है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में 9 राज्यों के चुनाव होने हैं। ऐसे में राहुल गांधी की हाल में खत्म हुई यात्रा एक भव्य पुरानी पार्टी को देर से ही सही उत्प्रेरित करने की जगह कुछ घमंडी महत्वाकांक्षा वाली परियोजना ही प्रतीत होती है।

सच है कि लोगों में सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर असंतोष है जैसा कि भारत जैसे एक विशाल और विविध लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन सत्तारूढ़ शासन के प्रति यह असंतोष छिटपुट ही है। पीड़ादायक आवाज को धैर्य पूर्वक सुनना एक बात है लेकिन ऐसी शिकायतों को एक कड़े राजनीतिक अभियान में पिरो कर उस आधार पर चुनाव जीतना एक कठिन काम है। वर्तमान में कांग्रेस ऐसे कार्यों को कर पाने में विफल ही दिखती है। क्योंकि यात्रा के दौरान भी विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने के बावजूद सहयात्री के रूप में विपक्षी दलों ने लगभग शामिल होने से इनकार कर दिया। एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए केंद्र में कांग्रेस के पास एक शक्तिशाली यूपीए होना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि इस दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है। इस तरह के प्रयासों के अभाव में संयुक्त भाजपा और खंडित विपक्ष के सामने सत्तारूढ़ एनडीए को 2024 में फिलहाल कोई चुनौती नहीं दिखाई देती है। यदा–कदा जो थोड़े बहुत असहमति के स्वर स्वर दिखाई देते हैं वह भी भाजपा के राष्ट्रवाद के मुकाबले बहुत ही कमजोर है।

उदयपुर चिंतन शिविर में संगठन को अधिक लोकतांत्रिक और युवा बनाने सहित संरचनात्मक सुधारों की बात की गई। भाजपा सरकार का काम भले ही अभी जमीन पर उतना नजर नहीं आ रहा है लेकिन जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का जोश भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस के जरिए विपक्षी एकता को अमलीजामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी सारी मेहनत दिनभर चले अढ़ाई कोस वाली ही है।

हालांकि कांग्रेस पार्टी 2024 की चुनौती से निपटने के लिए खुद को दो मुख्य मुद्दों पर तैयार कर रही है पहला संगठन को पुनर्जीवित करना और सक्रिय करना तथा दूसरा उस विचारधारा का प्रचार करना जिसमें पार्टी हमेशा से दृढ़ता से विश्वास करती रही है। अभी हाल ही में पार्टी को संबोधित करते हुए पार्टी के अध्यक्ष खड़गे ने कहा भी था कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की जिम्मेवारी कांग्रेस पर है। प्रत्येक भारतीय को यह महसूस करना चाहिए कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील और उदार भारत के सपनों को साकार करने का माध्यम रही है। कांग्रेस पार्टी को सभी भारतीयों को साथ लेकर इसके लिए आवाज उठानी चाहिए तथा कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कहने के लिए तो यह विचार बड़े ही अच्छे हैं लेकिन इसे क्रियान्वित कैसे किया जाए इसके लिए अब भी कांग्रेस के पास कोई रोडमैप नहीं है।

सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का मुकाबला एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी से है जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के नेतृत्व में भाजपा एक बहुत ही फिट, आक्रामक, जुझारू और चुनाव जीतने वाली मशीन की तरह है। भाजपा ने हाल ही में 200 सीटों में लगभग 130000 मतदान केंद्रों की पहचान की है जहां बीजेपी या तो कभी नहीं जीती है या बहुत कम अंतर से हारी है।भाजपा ने तय किया है कि ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक पूर्णकालिक प्रभारी होगा जो अगले लोकसभा चुनाव तक वही रहेगा। भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयारी की अवस्था में रहती है। सभी केंद्रीय मंत्रियों को निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद उन्हें केंद्र के प्रमुख कार्यक्रमों के वितरण और प्रसार की निगरानी करने का काम सौंपा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ लक्षित लोगों तक पहुंच रहा है अथवा नहीं। बीजेपी के अनुशासित संगठनात्मक तंत्र में चुनाव की तैयारियां हमेशा हरी बत्ती के मोड में होती है। राहुल गांधी का मुकाबला एक ऐसी सशक्त पार्टी से है जिसकी डिक्शनरी में हार मानना नहीं है। ऐसे में पदयात्रा से उत्साहित कांग्रेस पार्टीचुनाव में अपने पक्ष में कितने लोगों को सक्रिय कर पाती है यह तो भविष्य में पता चलेगा लेकिन मौजूदा संकेत यही बता रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए दिल्ली की यात्रा अभी न सिर्फ लंबी है बल्कि कठिन भी है। ❑❑

बढ़ते विदेश पलायन से उपजी आर्थिक चुनौती

गज़ब का विरोधाभास है, एक ओर भारत का लक्ष्य वर्ष 2027–28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने का है तो वहीं सवाल यह है कि फिर युवा, यहां तक अति–अमीर भी, बड़ी संख्या में देश से पलायन करने की कोशिश में क्यों लगे हैं? इससे ज्यादा अहम यह कि क्या वे इस संभावना को लेकर उत्साहित नहीं हैं कि जब कहा जा रहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर विश्व की मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रहेगी और जल्द ही जापान और जर्मनी को पछाड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी बन जाएगी। वह भी 2030 से पहले, जैसा कि वैश्विक बैंकिंग मूल्यांकन एजेंसी मॉर्गन स्टेन्ली द्वारा प्रस्तुत भविष्यवाणी दर्शा रही है। पिछले अनेक सालों से नीति–नियंताओं ने ऐसी नीतियां चलाईं जिससे गांवों से शहरों की ओर पलायन को बढ़ावा मिलता गया लेकिन इस पुरानी लीक की बजाय अब युवाओं ने प्रवास की नई राह पकड़ ली, गांव से सीधा विदेशी मुल्क।

भारत से न केवल युवा बल्कि अति–धनाढ्य भी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकता त्यागकर विदेशों में बसने के मौके तलाश रहे हैं। यह अति–धनी वह हैं, जिनके पास निवेश के लिए 10 लाख डॉलर से ज्यादा की तो केवल नगदी ही है। संसद को बताया गया है कि 2011 के बाद से 16 लाख से ज्यादा अमीरों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है, इनमें पिछले साल की 1,83,741 की संख्या शामिल है। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने हाल ही में संसद में कहा था कि वर्ष 2014–22 के बीच नौ सालों में 12.5–15 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है।

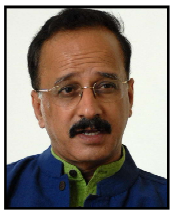

जब तक ध्यान का केंद्र पुनः शिक्षा स्तर सुधारने, सुलभ बनाने, वहन योग्य और गुणवत्तापूर्ण करने और व्याप्त बेरोजगारी संकट का निदान करने की ओर न होगा तब तक युवाओं को स्वदेश में बने रहकर अर्थव्यवस्था में भागीदारी बनने के लिए रोके रखने को प्रेरित करना संभव नहीं।

– देविन्दर शर्मा

मुझे तो लगता था कि अमीर लोग बाहर जाने की बजाय कुछ और इंतजार करना चुनते कि शायद अगले सालों में अर्थव्यवस्था और व्यापार के हालात में सुधार हो जाए, जिसका दावा सरकार कर रही है। लेकिन जब विकसित मुल्कों ने अति–धनाढ्यों के लिए निवेशक–श्रेणी के तहत अपनी सीधी नागरिकता देने की राह खोली तो भारत से धीरे–धीरे और ज्यादा गिनती में अमीर लोग बेहतर रहन–रहन और काम–धंधे के माहौल की खातिर विदेश जाकर बसने लगे। इस वर्ग के परिवारों के बाहर जा बसने से हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था को पड़ा घाटा विदेशी मुल्कों के लिए फायदेमंद बन गया।

बहरहाल, बात फिर से विदेशों की ओर पलायन करते युवाओं की चिंताजनक रूप से बढ़ती गिनती की करें, वह भी उच्च शिक्षा पाने के लिए, तो यह साफ दर्शाता है कि देश में शिक्षा का स्तर किस कदर सोचनीय है, तिस पर रोजगार के मौके भी यथेष्ट नहीं हैं, ऐसे में युवा विदेशों में अपना बेहतर भविष्य ताक रहे हैं। अफसोस, उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने की बजाय बहुत–सी राज्य सरकारें विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले इच्छुकों की मदद अलग ढंग से करने में लगी हैं। मसलन, पंजाब में यह सहायता अंग्रेजी की 'आइल्ट्स' परीक्षा के रूप में है।

उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्चों को विदेश भेजने वालों में अधिकांश वह हैं जिन्होंने इसकी खातिर अपने खेत बेचे या जायदाद गिरवी रखी या कर्ज उठाए हैं। विदेश में पढ़ाई करवाने का औसतन खर्च 25–30 लाख आता है अर्थात् घरेलू अर्थव्यवस्था से निकलकर इतना बड़ा धन विदेशी मुल्कों को मिल रहा है। डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के तहत विदेशों में शिक्षा प्राप्ति को मॉड–2 सेवा श्रेणी में बतौर उपभोक्ता व्यापार में रखा गया है (फिर भी दुनियाभर के देशों ने इसके लिए मुक्त आवागमन नहीं खोला)। इस प्रावधान ने युवा छात्रों को विदेशी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने की राह खोली, जिससे मेजबान मुल्क की अर्थव्यवस्था में इजाफा होता है।

विदेश जाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को यही उम्मीद रहती है कि आगे चलकर उसे वहां स्थाई तौर पर रहने की इजाजत मिल जाएगी। एक बेहतर रहन–सहन स्तर, ऊंची पगार और उच्च दर्जे की सामाजिक सुरक्षा इत्यादि वह अवयव हैं, जो छात्रों को विदेश जाने को लालायित करते हैं।

पिछले कई सालों से पंजाब, केरल और अब हरियाणा से भी, कुशल श्रमिकों का प्रवाह विदेशों को लगातार होता आया है। जहां पहले इन दोनों सूबों से जाने वाले मुख्यतयः काम–धंधा करने जाया करते थे वहीं अब ध्यान का केंद्र शिक्षा है। अकेले पंजाब से, तकरीबन 1. 5 लाख विद्यार्थी हर साल विदेश जा रहे हैं, केरल से यह संख्या लगभग 35000 है। अब तो हरियाणा में भी पढ़ाई के लिए विदेश जाने का चाव बढ़ने लगा है, वहां भी 'आइल्ट्स' करवाने और वीसा दिलवाने की 'दुकानें' दिखना आम दृश्य है।

विदेशों में पढ़ाई के लिए पहली पसंद कनाडा, अमेरिका, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और न्यूज़ीलैंड को है। जो बच्चे वहां प्रवेश पाने में सफल नहीं हो पाते वे रूस, जॉर्जिया, लात्विया, बेलारूस और उज़बेकिस्तान जैसे अनेकानेक पूरबी यूरोपियन देशों का रुख करते हैं। यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई के तुरंत बाद भारत सरकार को वहां पढ़ रहे लगभग 22500 छात्र, जिनमें अधिकांश मेडिकल शिक्षा ले रहे थे, किसी तरह निकालकर लाने का इंतजाम करना पड़ा था।

अब चाहे तो इसे 'ब्रेन–ड्रेन' कह लें, लेकिन पढ़ाई के लिए पंजाब, केरल और हरियाणा से विदेश जाने की दौड़ से जवान पीढ़ी की उपस्थिति में कमी हो रही है। इस दर पर, जल्द ही यह राज्य 'वृद्ध आश्रम' में तब्दील हो जाएंगे। वित्तीय भाषा में कहें तो इससे घरेलू मांग पर असर पड़ेगा। हमारी शिक्षा प्रणाली में व्याप्त कमियां और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की विफलता किस तरह समग्र विकास पाने में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है, इस पर एक समाचारपत्र के 4 जनवरी, 2023 अंक में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का रोचक लेख छपा है। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वे का हवाला देकर कहा है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 और 2019–21 के बीच, पांच सालों में, एक किसान के स्वामित्व वाले रकबे में औसतन 22 प्रतिशत की कमी हुई है। छोटे किसान की जोत भूमि भी 8.5 फीसदी सालाना घटी है। हालांकि यह डाटा सीधा तो सिद्ध नहीं करता किंतु संकेत साफ है कि ज्यादातर मामलों में यह कमी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का खातिर जमीन बेचने से बनी है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी (सीएमआईई) और अशोका यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि जनवरी, 2020 से अक्तूबर, 2022 के बीच, लगभग 3 सालों में, 1.2 करोड़ अतिरिक्त लोग बेरोजगार हुए हैं। सबसे अधिक प्रभाव 15–39 साल के युवा वर्ग पर पड़ा है। पहले की सीएमआईई की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में काम करने लायक 90 करोड़ लोगों की श्रमशक्ति में अधिकांश ने नौकरी की तलाश करनी बंद कर दी है। कुल मिलाकर देखें तो, यह युवाओं में बढ़ते मोहभंग का कारण दर्शाता है। यही वजह है कि विकास दर फिर से लय पकड़ेगी और अगले कुछ सालों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, ऐसे दावे युवाओं को आश्वस्त नहीं कर पा रहे।

सरल शब्दों में, केवल आर्थिकी का बढ़ना ही अकेला अवयव नहीं है जो बढ़ती आबादी की आकांक्षाएं पूरी कर सके। जब तक ध्यान का केंद्र पुनः शिक्षा स्तर सुधारने, सुलभ बनाने, वहन योग्य और गुणवत्तापूर्ण करने और व्याप्त बेरोजगारी संकट का निदान करने की ओर न होगा तब तक युवाओं को स्वदेश में बने रहकर अर्थव्यवस्था में भागीदारी बनने के लिए रोके रखने को प्रेरित करना संभव नहीं। यह एक चुनौती है और पूरी तरह से सरकार के संसाधनों के भीतर भी, बशर्ते कि वास्तव में सारा जोर 'सबका साथकृ सबका विकास' नारे को फलीभूत करने पर लगाया जाए। ❑❑

लेखक कृषि एवं खाद्य मामलों के विशेषज्ञ हैं।

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/economic-challenge-arising-out-of-increasing-migration-abroad-136321

हरित अनुबंध पत्र (ग्रीन बॉन्ड)

पर्यावरण हमारे जीवन की पद्धति और आधार है। श्री मदभागवत गीता में भगवान कृष्ण ने प्रकृति के पाँच तत्वों के स्थान पर आठ तत्वों का उल्लेख किया है यथा *''भूमिरापोनलो वायुः खं मनो बुद्धि रेवच। अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।।''* (श्रीमद्भागवद् गीता अ–7/4)।

पर्यावरण–सन्तुलन से तात्पर्य है जीवों के आसपास की समस्त जैविक एवं अजैविक परिस्थितियों के बीच पूर्ण सामंजस्य। वर्तमान कालखंड में औद्योगिक क्रांतियों के अलग अलग चरणों में मानव उपभोग हेतु विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए जिन मशीनों और प्रक्रियाओं की रचना की गयी उनमें ईंधन के रूप में कोयला, पेट्रोल, डीजल के प्रयोग को आधार रख कर ही उत्पादन की नींव रखी गयी जिसका विनाशकरी रूप आज हम सब को यह सोचने और कार्यान्वित करने को विवश का रहा है की हम अपनी औद्योगिक संरचना को परिवर्तित करें और मानव जीवन की रक्षा के लिए ऊर्जा के हरित और अक्षय संसाधनों के अनुरूप न केवल देश में बल्कि विश्व में अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों को अपनाएं। हरित और अक्षय ऊर्जा से तात्पर्य है – सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन आदि जो विषाक्त गैसों का उत्सर्जन नहीं करते। यह इतना सरल नहीं है। सरकार और व्यक्तिगत स्तर पर दीर्घकालीन योजना, शोध, नवोन्मेष और निवेश की बहुत बड़े पैमाने पर आवश्यकता है। कॉप 26 और 27 के सम्मेलनों में सभी देशों के लिए लक्ष्य नियत किए गए और उनके अनुपालन की बाध्यता तय की गयी। वैश्विक मानक जो भी हों परंतु पर्यावरण की चिंता हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है और प्रकृति का आक्रोश बहुत विनाशकारी है जैसा हम बार बार विभिन्न देशों में बाढ़, सूखा, ग्लाशियरों का पिघलना, पर्वतों पर स्ल्खन, भूकंप, सुनामी की विनाशलीला देख रहे है।

हरित परियोजनाओं और बॉण्डों के लिये क्रेडिट रेटिंग या रेटिंग दिशा–निर्देशों के लिए भी प्रावधान करने की आवश्यकता है। सरकार की इस पहल का समर्थन करने की इच्छा रखने वाले निवेशकों को अपने साथ जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि जुटाए गए फंड का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ही किया जाए।

–विनोद जौहरी

1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट वित्त वर्ष 2022–23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कई बड़े फैसलों की घोषणा की। वर्ष 2022–23 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी कर ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए रिसोर्सेज जुटाने की बात कही थी। यह वित्त मंत्रालय के अनुसार 2021 में ग्लासगो में कॉप–26 में पीएम मोदी की दृष्टि "पंचामृत" के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरुप है। सरकार ने गत वर्ष एक व्यापक नोट जारी किया था और इस विषय में विस्तार से जानकारी दी थी। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि उसने संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधित्व के साथ ग्रीन फाइनैंस वर्किंग कमेटी का गठन किया है। कमेटी की अध्यक्षता भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार करेंगे। यह कमेटी एक वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करेगी जिसमें आवंटन, परियोजना का विस्तार से ब्योरा, क्रियान्वयन की स्थिति तथा आवंटित न हो सकी, प्राप्तियों का ब्योरा होगा।

ग्रीन बॉण्ड ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से ग्रीन परियोजनाओं के लिये धन जुटाया जाता है, यह मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है। बॉण्ड जो कि आय का एक निश्चित साधन होता है, एक निवेशक द्वारा उधारकर्त्ता (आमतौर पर कॉर्पोरेट या सरकारी) को दिये गए ऋण का प्रतिनिधित्व करता है। पारंपरिक बॉण्ड (ग्रीन बॉण्ड के अलावा अन्य बॉण्ड) द्वारा निवेशकों को एक निश्चित

ब्याज दर (कूपन) का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2007 में यूरोपीय निवेश बैंक और विश्व बैंक जैसे कुछ बैंकों द्वारा ग्रीन बॉण्ड लॉन्च किया गया। इसके बाद वर्ष 2013 में कॉरपोरेट्स द्वारा भी इन्हें जारी किया गया जिस कारण इसका समग्र विकास हुआ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा ग्रीन बॉण्ड जारी करने एवं इन्हें सूचीबद्ध करने हेतु पारदर्शी मानदंडों को लागू किया गया है।

आमतौर पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की तुलना में ग्रीन बॉण्ड पर कम ब्याज लिया जाता है। हरित निवेश विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के साथ–साथ पूंजी जुटाने की लागत को कम करने में मदद कर सकता है। ग्रीन बॉण्ड अक्षय ऊर्जा जैसे सनराइज़ सेक्टर के वित्तपोषण को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण रहे हैं, इस प्रकार यह भारत के सतत् विकास में योगदान देते हैं।

ग्रीन बॉन्ड विभिन्न श्रेणियों– अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा कुशलता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन, टिकाऊ जल एवं कचरा प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण, ग्रीन बिल्डिंग्स, प्राकृतिक संसाधनों एवं जमीन के इस्तेमाल का टिकाऊ प्रबंधन और स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण, ऊर्जा सक्षम भवनों, सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण, जलवायु के अनुकूल बुनियादी ढांचे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, भूमि और समुद्री जैव विविधता परियोजनाओं हेतु हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2023 के अंतिम सप्ताह में पहली बार भारत सरकार की ओर से 8,000 करोड़ रुपये मूल्य के सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किए। ऐसे निवेशक हैं जो हरित पहल का समर्थन करने के लिए अपेक्षाकृत कम प्रतिफल के लिए राजी हैं। कुछ संस्थागत निवेशकों के लिए यह आवश्यक किया गया है कि वे अपने फंड का एक भाग ऐसी योजनाओं में निवेश करें। यही

हरित निवेश विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के साथ-साथ पूंजी जुटाने की लागत को कम करने में मदद कर सकता है। ग्रीन बॉण्ड अक्षय ऊर्जा जैसे सनराइज़ सेक्टर के वित्तपोषण को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण रहे हैं, इस प्रकार यह भारत के सतत् विकास में योगदान देते हैं।

कारण है कि हरित कारोबार में लगे निकाय अपेक्षाकृत कम दरों पर फंड जुटाने में कामयाब हैं। वैश्विक स्तर पर सरकारों ने अब तक हरित बॉन्ड का सीमित इस्तेमाल किया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2022 के नोट में प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2022 के बीच जारी किए गए कुल बॉन्ड में सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड केवल 2 फीसदी थे।

भारत सरकार ने 5 और 10 वर्षों की प्रतिभूतियों के रूप में ग्रीन बॉन्ड जारी किए। पहली नीलामी में प्रतिफल समान अवधि के नियमित बॉन्ड की तुलना में 5–6 आधार अंक तक कम था। इस अंतर को ग्रीनियम कहा जाता है। आईएमएफ द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी डॉलर वाले बॉन्ड में उभरते बाजारों के लिए ग्रीनियम 49 आधार अंकों के बराबर था। यह दर्शाता है कि प्रारंभ में अंतर कम था जो समय के साथ बढ़ता गया। ऐसे में यह संभव है कि इस प्रकार के बॉन्ड की मांग बढ़ने के साथ ही आरबीआई इसकी अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत तय कर सकेगा। ग्रीन बॉन्ड की पहली खेप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा जमकर खरीदी गई थी। सूचना के अनुसार संस्थागत विदेशी निवेशकों ने भी करीब 700 करोड़ रुपये मूल्य के ग्रीन बॉन्ड खरीदे।

यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण होगा कि इस फंड का इस्तेमाल उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया जाए। प्राप्तियों को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा जो यह हरित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगा। वित्त मंत्रालय इसके लिए एक अलग खाते की व्यवस्था करेगा। वह एक ग्रीन रजिस्टर भी बनाएगा जिसमें फंड के जारी होने और आवंटन की जानकारी रखी जाएगी। सरकार का इरादा तृतीय पक्ष के समीक्षकों को जोड़ने का भी है ताकि वे सालाना आकलन पेश कर सकें। इस ढांचे का पारदर्शी क्रियान्वयन जरूरी हरित बदलाव की दिशा में सरकार की उधारी की लागत कम करने में मदद करेगा।

सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक ग्रीन बॉण्ड बाज़ार को विकसित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दिशा–निर्देशों एवं मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। ग्रीन बॉण्ड के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश निजी निवेश को आकर्षित करने और साथ ही ग्रीन बॉण्ड बाज़ार में निवेशकों का विश्वास स्थापित करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लक्षित परियोजनाएं पर्याप्त रूप से हरित परियोजनाएँ ही हैं क्योंकि ग्रीन बॉण्ड से प्राप्त आय का उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु किया जा रहा है। हरित परियोजनाओं और बॉण्डों के लिये क्रेडिट रेटिंग या रेटिंग दिशा–निर्देशों के लिए भी प्रावधान करने की आवश्यकता है। सरकार की इस पहल का समर्थन करने की इच्छा रखने वाले निवेशकों को अपने साथ जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि जुटाए गए फंड का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ही किया जाए। ❑❑

विनोद जौहरी: सेवानिवृत अपर आयकर आयुक्त

तेजी से बदलता ग्रामीण भारत

भारत को गांव का देश कहा गया और कृषि को उसकी रीढ़, जो आधी से ज्यादा आबादी को आजीविका मुहैया कराती है। देश के आधे से ज्यादा लघु और कुटीर उद्योग की जड़े भी गांव में ही है। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत को जानना है तो गांव को जानना पड़ेगा और स्वराज का सपना इन्हीं गांवो से ही पूरा होगा।

अंग्रेजी शासन के दौरान गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मैटकाफ ने अपने हुक्मरान को भेजें खत में लिखा था कि भारत के गांव अपने आप में छोटे–छोटे गणराज्य हैं, जो अपनी जरूरत की चीजों की व्यवस्था खुद कर लेते हैं। हमारी ग्रामीण व्यवस्था देख कर अंग्रेज वाकई हैरान थे। असल में गांव शहरों के लिए हमेशा अन्नदाता की भूमिका में रहे लेकिन आर्थिक मॉडलों के तहत उन्हें शहरों पर निर्भर कर दिया गया। यही कारण है कि ग्रामीण व्यवस्था की आत्मनिर्भरता धीरे–धीरे कमजोर होती गई।

करीब साढे 6 लाख गांव के समृद्ध ताने–बाने से बुने भारत के सामाजिक, आर्थिक परिवेश में ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण जनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।आज भी हमारे देश की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। इसलिए भारत की रीढ़ कहे जाने वाले गांव के विकास के बिना देश के संपूर्ण विकास की कल्पना निरर्थक है, फिर भी अपने पहलू में अनमोल सांस्कृतिक विरासत और विविधता को समेटने वाले भारत के गांवों को शहरों की तुलना में हमेशा ही अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आज जब देश गणतंत्र का 73वां बसंत मना रहा है तब यह जानना जरूरी हो जाता है की आजादी के समय की भूखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी और बीमारियों का प्रकोप झेल रहा ग्रामीण भारत आज के इस डिजिटल युग में विकास के किस मोड़ पर खड़ा है और हमारी सरकारों ने ग्रामीण विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं?

हमें यह याद रखना होगा कि दुनिया को शून्य जैसी महान सौगात देने वाली 5000 साल पुरानी सभ्यता वाले भारत को शून्य से ही अपनी शुरुआत करनी पड़ी थी। क्रांतिकारियों की शहादत आंदोलनकारियों की कुर्बानियां और करोड़ों देशवासियों के अथक परिश्रम का अनमोल लम्हा रहा जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तब से लेकर अब तक का एक लंबा सफर देश ने तय किया है। आजादी के बाद का दौर प्रारंभ में आशंकाओं से भरा हुआ था लेकिन उन सारी कठिनाइयों को पार कर आज भारत उपलब्धियों के साथ

"आज देश में स्वच्छता एक मिशन बन गया है। कमजोर तबके का बैंक से सीधे रिश्ता कायम हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए समाज की सोच भी बेटियों के प्रति धीरे–धीरे बदल रही है।

– शिवनंदन लाल

विश्व की उम्मीद बनकर खड़ा है। आजादी के बाद भारत के सामने अनेकों चुनौतियां रही है लेकिन उन्हें पीछे छोड़ते हुए भारत ने दुनिया में अपना जो श्रेष्ठ स्थान बनाया है उसकी मिसाल कम ही मिलती है। आजादी के अमृत काल में जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि इन वर्षों में देश में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए सफलता के कई परचम लहराए है।

आजादी के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग–अलग रियासतों का भारत में विलय कर तथा राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती प्रदान करते हुए सशक्त और समर्थ राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। नतीजा हुआ कि पिछले 7 दशकों में हमारे देश ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर एक अनूठी मिसाल कायम की है। देश में किसानों की उपज बढ़ गई है और उनकी आय में भी पहले से इजाफा हुआ है। देश में श्वेत क्रांति से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और इसी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है।

आजादी से पहले ग्रामीण भारत की जनसंख्या लगभग 85 प्रतिशत थी, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी आय के लिए कृषि पर निर्भर थी। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र की स्थिति अत्यंत खराब थी। इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमीदारी, रैयतवारी जैसी भू व्यवस्था प्रणालियां थी। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं का अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए जिम्मेदार था। जानकर दुख होगा कि पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकतर भारतीय भुखमरी के कगार पर रहते थे। गरीबी और भूखमरी की जड़ें भारत में कितनी गहरी हो गई थी इसका अंदाजा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़े अकाल से लगाया जा सकता है। एक ब्रिटिश लेखक विलियम डिगबी ने हिसाब लगाया कि 1854 से 1901 तक कुल मिलाकर दो करोड़ 88 लाख 25 हजार से अधिक लोग अकाल से मर गए थे। कृषि व्यवस्था इस हाल में पहुंच गई थी कि स्वतंत्रता के समय तक देश अनाज की कमी से जूझ रहा था। आजादी के बाद भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भूमि सुधार, कृषि सुधार, हरित क्रांति, प्रौद्योगिक नवाचार मशीनीकरण समेत अनेक कदम उठाए गए। वर्तमान में खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान दूसरा है। आज भी 58 प्रतिशत परिवार आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं और आर्थिक सर्वे के अनुसार कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18 प्रतिशत का योगदान है।

आजादी के पहले ब्रिटिश शासन में शिक्षा प्रणाली में आम जनता की शिक्षा की उपेक्षा की गई। अंग्रेजों ने उच्च और मध्यम वर्गों के कुछ भारतीयों को ही शिक्षित करने पर ध्यान दिया था। परिणाम यह हुआ कि 1911 में 94 प्रतिशत और 1921 में 92 प्रतिशत भारतीय जनता निरक्षर थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने प्रारंभिक शिक्षा नीति में लड़कियों की शिक्षा के लिए भी धन की कोई व्यवस्था नहीं की जिसके चलते 1921 में केवल 2 प्रतिशत भारतीय स्त्रियां ऐसी थी जिन्हें पढ़ना लिखना आता था।अंग्रेजी हुकूमत ने ग्रामीण शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्वतंत्रता के समय यानी वर्ष 1947 में महिलाओं की समग्र साक्षरता दर देश में 6 प्रतिशत थी। आज ग्रामीण भारत की साक्षरता दर लगभग 73 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 81 प्रतिशत और महिलाओं की 65 प्रतिशत के आसपास हो गई है।

19वीं सदी का भारत सफाई, जन स्वास्थ्य, जलापूर्ति जैसी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में पिछड़ा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपनी आय का अधिकांश भाग सेना, युद्ध और प्रशासकीय सेवाओं पर खर्च कर देती थी। सामाजिक सेवाओं के लिए खर्च होने वाला बजट इतना कम होता था कि आज कोविड जैसी महामारी से निपटने वाला भारत उस समय हैजा, चेचक जैसी मामूली बीमारियों के सामने घुटने टेक देता था। इस तरह की बीमारियों महामारियो का प्रकोप सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही झेलना पड़ता था। इंपीरियल गजट ऑफ इंडिया के अनुसार साल 1881 से 1890 के बीच भारत में हैजा, चेचक, ज्वर, अतिसार, प्लेग और अन्य बीमारियों से देश के विभिन्न हिस्सों में 49 लाख 86 हजार 950 लोग मर गए थे। समय के साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया गया और वर्तमान में सभी ग्रामीणों तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहुंच सुनिश्चित करने, हर व्यक्ति की सेहत का डाटा एकत्र करने, रोग के पूर्व निदान में स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटल अवतार कारगर साबित हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति का ही नतीजा है कि आज एक भारतीय की जीवन प्रत्याशा 32 साल से बढ़कर 70 साल तक की हो गई है।

अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में परंपरागत उद्योगों का पतन हुआ, किंतु आधुनिक मशीन उद्योगों का विकास नहीं हुआ, जिससे हस्तशिल्प और दस्तकार तबाह हो गए और गांव में आर्थिक जीवन असंतुलित हो गया। साल 1946 के दौरान कारखानों में काम करने वाले 40 प्रतिशत मजदूर सूती कपड़ा और जूट उद्योग में लगे हुए थे। भारत के औद्योगीकरण की शून्यता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि वर्ष 1951 में 35 करोड़ 70 लाख की कुल जनसंख्या में से केवल 23 लाख लोग आधुनिक औद्योगिक उद्यमों में लगे थे।आज देश में 6.3 करोड़ एमएसएमई लघु उद्योग कार्यरत हैं जिनमें से 20 प्रतिशत

एमएसएमई का केंद्र गांव में है। लघु उद्योगों की एक विशेषता यह है कि इसका बड़ा हिस्सा 6000 संभावित समूहों, 11057 पारंपरिक औद्योगिक समूहो, 3091 हस्तशिल्प समूहों और 563 हथकरघा समूहों के इर्द–गिर्द केंद्रित है। यह कृषि के बाद कम पूंजी लागत पर सबसे अधिक रोजगार देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र गैर कृषि आजीविका, संतुलित क्षेत्रीय विकास, लिंग और सामाजिक संतुलन तथा स्थाई समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

अक्टूबर 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना, अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना, 20 अगस्त 2014 को डिजिटल भारत, 16 अक्टूबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, 16 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन, 16 नवंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए।

14 अप्रैल 2016 से शुरू राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई–नाम के द्वारा कृषि उत्पादन के लिए बेहतर कारोबारी अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इसके अंतर्गत सभी सेवाएं सम्मिलित की जाती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के दौरान करनी पड़ती है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप सहित कई एक सिंचाई सुविधा योजना के साथ–साथ गांव में डिजिटल अवसंरचना को गति मिलने से स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय शासन तंत्र और बैंकिंग सेवाओं आदि का दायरा बढ़ा है। डिजिटल पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी और गांव की चौपाल तक डिलीवरी ब्वॉय की पहुंच, ग्रामीण भारत में डिजिटल पद चिन्हों के बढ़ने के ही परिणाम है।गांव के प्राकृतिक परिवेश और सरल जीवन में पर्यटकों को आत्मिक आनंद मिलता है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलने से रोजगार व आमदनी के साथ–साथ गांव का सांस्कृतिक व सामाजिक विकास भी होता है। वर्तमान में इस क्षेत्र में सभी संभावनाओं को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है।

आज देश में स्वच्छता एक मिशन बन गया है। कमजोर तबके का बैंक से सीधे रिश्ता कायम हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए समाज की सोच भी बेटियों के प्रति धीरे–धीरे बदल रही है। भारत में स्टार्टअप और स्टैंडअप की राह आसान हुई है। डिजिटल इंडिया का सपना साकार हुआ है। स्किल इंडिया से रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल हुआ है। किसानों की प्रगति का नया सफर, मुद्रा के जरिए छोटे व्यापारियों की उड़ान, गंगा को निर्मल बनाने की कोशिश, आयुष्मान भारत से स्वस्थ समाज की उम्मीदों के साथ लगभग 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नए भारत के निर्माण की दिशा में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है।

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक आत्मनिर्भर अभियान गांव से ही परिपूर्ण हो सकता है। आज भी 60 करोड़ से ज्यादा लोग खेती और ग्रामीण उद्योग से जुड़े हैं, लेकिन उनकी तुलना में खेती पर सरकारी खर्च बहुत कम है। आरबीआई के अनुसार वर्ष 2011–12 से लेकर 18–19 के दौरान जीडीपी का 0.4 प्रतिशत ही कृषि पर खर्च हुआ।

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए आजादी के बाद से अब तक कई प्रयास किए गए हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक ढांचे में आमूलचूल बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन यह बदलाव पर्याप्त नहीं है। आज भी देश के कई गांव को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, तकनीकी एवं औद्योगिक समृद्धि का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार को अपनी योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के साथ उन्हें धरातल पर लागू करना होगा। जब प्रत्येक गांव गरीबी से मुक्त, उन्नत आजीविका के साथ सामाजिक रूप से सक्षम बनेगा तभी देश का मुकम्मल विकास संभव होगा। ❑❑

(वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी नई दिल्ली केंद्र)

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

28 जनवरी, 2023

प्रेस विज्ञप्ति

पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र घोषित हो हिमालय

(हमारे इतिहास, संस्कृति और समृद्ध विरासत का हिस्सा, जोशीमठ डूबने के कगार पर है।)

श्री आदि शंकराचार्य ने आठवीं शताब्दी में जिस जगह पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, उसे जोशी मठ (ज्योतिर्मठ) के नाम से जाना जाता है। आज यह मठ टूटने के कगार पर है। जोशी मठ के डूबने की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भले ही मौजूदा संकट को देखते हुए कुछ कदम उठाए गए हों, लेकिन जानकारों का मानना है कि भविष्य में जोशी मठ को डूबने से नहीं रोका जा सकता है। अर्थात आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित इस प्रथम ज्योतिर्मठ का पतन अवश्यंभावी है।

आज हम यहां जोशीमठ के जमीनी तथ्यों और यहां से अगले कदमों पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं।

1. मौजूदा मुद्दा: इस साल की शुरुआत में जोशीमठ में अचानक जमीन धंसने की घटना ने सबका ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन अतीत में आयी तमाम कई सरकारी रिपोर्टों के माध्यम से इस तरह की घटना की चेतावनी पूर्व में ही दी गई थी।

इस क्रम में वर्ष 1976 में आयी मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में जोशीमठ/ऊपरी अलकनंदा बेसिन के आसपास के इलाकों को अति नाजुक श्रेणी में रखते हुए जोशीमठ शहर के 5 किमी के दायरे में निर्माण सामग्री एकत्र करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि खुदाई या विस्फोट से कोई बोल्डर नहीं हटाया जाना चाहिए और भूस्खलन क्षेत्र में कोई पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा था कि जोशीमठ शहर नाजुक फिसलने वाले क्षेत्र में स्थित है।

इसी तरह वर्ष 2010 में योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि "नो गो" क्षेत्रों को परिभाषित करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2013 की आपदा के बाद विशेषज्ञ निकाय समिति की रिपोर्ट कहती है कि ये नाजुक पहाड़ अत्यधिक बोझिल हैं और वनों की कटाई और इन क्षेत्रों की वहन क्षमता से अधिक निर्माण कार्य आपदाओं के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं।

2. मूल कारण का आकलन: हिमालय क्षेत्र में इस तरह की त्रासदी पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले साल 2021 में भी तपोवन बांध के मजदूरों समेत 200 लोगों की चमोली की बाढ़ में मौत हो गई थी। इससे पहले 2013 में भी भारी बारिश के बाद क्षेत्र में गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों में आई बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में पुल, सड़कें और इमारतें ढह गई थी। हाल के वर्षों में हिमालयी क्षेत्र में ऐसी आपदाओं की संख्या में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई है। इन प्राकृतिक आपदाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

ऐसे नाजुक इलाके में अनियंत्रित निर्माण कार्य जोशी मठ के ढहने और हाल की आपदाओं का कारण है। गौरतलब है कि जिस तरह से चार धाम मार्ग के निर्माण के लिए जोशी मठ की तलहटी में पहाड़ को काटा गया और बिना हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी के एनटीपीसी ने अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ के बीच में सुरंग खोद दी, उससे यह नाजुक पहाड़ नष्ट हो गया। यह भी देखा गया है कि बहुमंजिली होटलों और भवनों के मजबूत और अनियोजित निर्माण के कारण स्वच्छता की व्यवस्था अपर्याप्त है, जो जोशीमठ को और अधिक अस्थिर और बोझिल बनाता है। इन सबके कारण आज जोशी मठ का पूरा क्षेत्र डूब रहा है और उसे बचाने का कोई उपाय नहीं है।

सवाल सिर्फ जोशी मठ का नहीं है। पूरे उत्तराखंड में विकास के नाम पर निर्माण कार्य और प्रकृति से छेड़छाड़ लगातार हो रही है। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण पहाड़ों पर शायद ही कोई हरियाली बची है; और इस वजह से इन सबसे बने नये पहाड़ों में भूस्खलन आम बात हो गई है।

3. अपर्याप्त समाधान: जोशी मठ नगरी डूबने से जहां एक ओर बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रभावित निवासियों के पुनर्वास के माध्यम से ही समाधान खोजा जा रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र की मेगा परियोजनाओं – नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जलविद्युत परियोजना, हेलंग बाईपास सड़क निर्माण, जो कि चारधाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना के नाम से जानी जाती है और रोपवे परियोजना को स्थानीय विरोध के आगे जिला प्रशासन ने फिलहाल रोक दिया है।

यह देखा जा सकता है कि भागीरथी ईएसजेड जैसे क्षेत्र, जहां बड़े पैमाने पर मेगा परियोजनाएं नहीं हुई हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, वहां भूमि धंसाव और भूस्खलन की घटनाएं और विनाशकारी आपदा घटनाएं न्यूनतम हैं। यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि उत्तराखंड राज्य में अंधाधुंध अनियोजित मजबूत निर्माण ने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से आपदा जैसी स्थिति को प्रभावित किया है।

अतीत में हुए इस प्रकार के तीव्र विनाश को देखते हुए यह विचार करना आवश्यक हो गया है कि मानवीय लालच से प्रेरित तथाकथित विकास को अब आगे और जारी नहीं रहने दिया जा सकता। पूरा उत्तराखंड और खासकर नैनीताल व मसूरी आदि पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र भी डूबने की कगार पर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जल्द ही नैनीताल और गढ़वाल के अन्य इलाकों में भी जोशी मठ जैसी स्थिति दोहराई जा सकती है।

गौरतलब है कि पिछले दो दशकों में उत्तराखंड और अन्य पहाड़ी राज्यों में भी सड़कों के चौड़ीकरण, सुरंगों, रेलवे लाइनों, बांधों के निर्माण के साथ–साथ बड़े पैमाने पर भवन निर्माण, जिसमें ज्यादातर होटल निर्माण शामिल है, का काम तेज गति से बढ़ा है। इस दौरान केंद्र और राज्य में अलग–अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं। इसलिए इन आपदाओं के लिए अकेले किसी एक राजनीतिक दल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

4. समाधान क्या है? अपेक्षित प्रभाव का आकलन किए बिना विकास के नाम पर विनाशकारी निर्माण आज और पहले की त्रासदियों का कारण बन रहा है। इस अंधाधुंध निर्माण पर रोक लगाकर ही इस संकट से बचा जा सकता है। लेकिन अलग–अलग जगहों पर हो रहे निर्माण कार्यों को बिना कानून बनाए रोका नहीं जा सकता।

विधान एक लंबी प्रक्रिया है और विभिन्न हितधारकों के बीच राय की सहमति बनाना एक कठिन कार्य है। इसके लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रयास कर सकती है। वर्तमान संकट के कारण जिला प्रशासन ने सभी निर्माण गतिविधियों को बंद कर दिया है, लेकिन यदि दीर्घकालीन उपायों पर विचार नहीं किया गया तो देर–सबेर ये निर्माण कार्य फिर से शुरू हो जायेंगे। इसलिए जरूरी है कि इस समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालीन उपाय किए जाएं। हम जानते हैं कि देश की अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। जबकि हिमालय के शीर्ष पर ग्लेशियर हैं। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इससे न केवल पानी के अधिक प्रवाह के कारण पीने के पानी के स्रोत कम हो रहे हैं, बल्कि समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है।

हिमालय को इको सेंसिटिव जोन घोषित करें

विभिन्न नदियाँ ग्लेशियर के नीचे से निकलती हैं। पूर्व में गंगा नदी पर बांध बनाने के नाम पर प्र.ति से छेड़छाड़ कर गंगा की अविरल धारा को बाधित करने का विरोध होता रहा है। प्रो. जीडी अग्रवाल सहित कई लोगों के विरोध और आंदोलन और आमरण अनशन के बाद, वर्ष 2010 में, केंद्र सरकार ने भागीरथी के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। उसके बाद का अनुभव है कि उस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं लगभग न के बराबर रही हैं। इसी प्रकार भागीरथी क्षेत्र के समानांतर यदि यमुनोत्री, अलकनंदा, मंदाकिनी तथा काली नदी एवं धौली गंगा क्षेत्रों को भी ईको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए तभी इस क्षेत्र में भविष्य में होने वाली आपदाओं को रोका जा सकेगा।

बड़ी परियोजनाओं की तबाही को नियंत्रित करने के लिए चारधाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना से इलाके की क्षति को कम करने के लिए सड़क की चौड़ाई को मध्यवर्ती मानक तक विनियमित करना चाहिए।

चारधाम रेलवे एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना है जो बहुत तबाही मचाएगी और उत्तराखंड के पर्यटक केंद्रित राज्य पर और अधिक बोझ डालेगी। इस परियोजना का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और फिर से देखा जाना चाहिए।

उत्तराखंड राज्य की वहन क्षमता का विस्तृत आकलन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन स्थानों पर पर्यटकों की संख्या प्रकृति के अनुकूल रखी जाए ताकि इससे पर्यावरण पर अत्यधिक बोझ न पड़े।

गंगा बेसिन पूरे देश की सामूहिक संपत्ति है और गंगा हिमालय की सांस्कृतिक पवित्रता त्रुटिहीन है। इससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इन पारिस्थितिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का ध्यान में रखते हुए इसे एक अंतर–पीढ़ीगत इक्विटी के रूप में सुरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए।

यह समझना होगा कि वर्तमान पीढ़ी और सरकार पर न केवल हिमालय क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, बल्कि इस भूमि पर रहने वाले उन सभी लोगों के भविष्य की भी जिम्मेदारी है, जो इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियों पर निर्भर हैं। केंद्र और राज्य दोनों की वर्तमान सरकारों को अत्यंत संवेदनशीलता दिखानी होगी, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

डॉ अश्वनी महाजन (राष्ट्रीय सह संयोजक)

बचत पर चोट है नई टैक्स प्रणाली

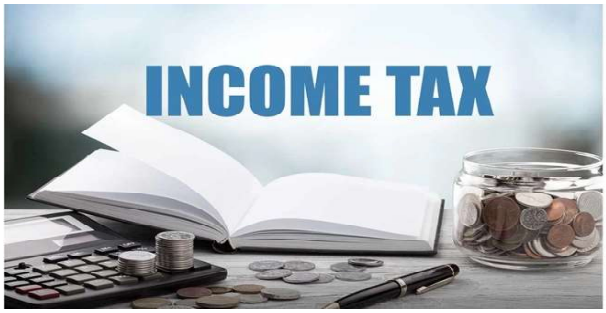

स्वदेशी जागरण मंच ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने बजट भाषण में घोषित कर छूट पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोगों की बचत को प्रभावित करेगा, जो सरकारी उधारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। संगठन ने यह भी कहा है कि बजट ऐसे समय में विनिर्माण क्षेत्र को पर्याप्त समर्थन प्रदान नहीं करता है, जब चीन से भारत का आयात "अभूतपूर्व" उच्च स्तर पर है।

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि "स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि नई आयकर प्रणाली करदाताओं को कम कर बोझ के साथ रिटर्न दाखिल करने में आसानी के मामले में राहत दे सकती है; लेकिन इसका आयकरदाताओं द्वारा की जा रही बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।" उन्होंने कहा, "एसजेएम सरकार पर मध्यम वर्ग द्वारा बचत को बढ़ावा देने के लिए कर व्यवस्था को बदलने के लिए दबाव बनाएगा। क्योंकि यह सरकार के उधार और पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।"

डॉ. महाजन ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए बजट प्रोत्साहन को अपेक्षाओं से कम पाया है। हालांकि यह उम्मीद थी कि इस बजट में विनिर्माण पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसजेएम बजट में पर्याप्त प्रयासों की कमी पर अपना असंतोष व्यक्त करता है। उसमें उत्पादों पर टैरिफ की बढ़ोतरी और मध्यवर्ती उत्पाद शामिल हैं। आज देश चीन से अभूतपूर्व मात्रा में आयात और व्यापार घाटा देख रहा है, लेकिन वित्त मंत्री का इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं जा सका।

सरकारी व्यय के बारे में बात करते हुए डॉ. महाजन ने कहा, "वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, कुल व्यय लगभग 42 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। इसकी तुलना में इस साल करीब 45 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान (बजट अनुमान) रखा गया है, यानी सिर्फ 7 फीसदी की बढ़ोतरी।

डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि शायद राजकोषीय घाटे को 5.9 प्रतिशत तक सीमित करने के उद्देश्य से व्यय को सीमित किया गया है। हालांकि पूंजीगत व्यय पर राजकोषीय व्यय का बोझ महसूस नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'बल्कि कैपेक्स में बढ़ोतरी बजट का स्वागत योग्य हिस्सा है।' कुल मिलाकर, एसजेएम ने बजट को विवेकपूर्ण और विकासोन्मुखी पाया है जिसमें एमएसएमई, कृषि और पर्यटन को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान की है।

https://www.jansatta.com/national/rss-affiliate-swadeshi-jagran-manch-not-happy-with-budget-2023-new-tax-regime-hits-savings/2640936/

ईको सेंसिटिव जोन घोषित हो हिमालय

विशेषज्ञों ने हिमालय को एक पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की मांग करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में विकास के नाम पर अनियोजित और अनियंत्रित निर्माण ने जोशीमठ को डूबने के कगार पर ला दिया है। स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) द्वारा शनिवार को आयोजित एक गोलमेज बैठक में पारित एक प्रस्ताव में विशेषज्ञों ने बाढ़ प्रभावित जोशीमठ में मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को "अपर्याप्त" करार दिया है।

बैठक में सरकार से समस्या के समाधान के लिए लॉन्ग टर्म उपाय करने पर विचार करने के लिए भी कहा। विशेषज्ञों ने कहा कि अगर मानव लालच से प्रेरित तथाकथित विकास की जांच नहीं की जाती है तो नैनीताल, मसूरी और गढ़वाल के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि हिमालय को एक पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि तबाही मचाने वाली बड़ी परियोजनाओं को विनियमित करने पर नुकसान कम हो सके। चार धाम रेलवे परियोजना का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड की एक विस्तृत वहन क्षमता का आकलन किया जाना चाहिए कि इन स्थानों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या का हिसाब रखा जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पर्यटकों के फ्लो से पर्यावरण पर बोझ न पड़े। 'इमीनेट हिमालयन क्राइसिस' विषय पर विचार–विमर्श के लिए आयोजित गोलमेज सम्मेलन में केंद्र की चार धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के पूर्व अध्यक्ष रवि चोपड़ा, इसके पूर्व सदस्य हेमंत ध्यानी और एसजेएम के सह–संयोजक अश्वनी महाजन ने भाग लिया।

https://www.aajtak.in/india/news/story/steps-taken-in-subsidence-hit-joshimath-inadequate-declare-himalayas-eco-sensitive-zone-says-experts-ntc-1625651-2023-01-29?utm_source=atweb_story_share

रॉयल्टी भुगतान पर फिर से लगे रोकः एसजेएम

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने केंद्र से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर से किए जाने वाले रॉयल्टी भुगतान पर फिर से रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि इससे बड़ी धनराशि देश से बाहर जा रही है।

एसजेएम ने कहा कि 2009 में रॉयल्टी भुगतान पर लगी रोक हटाए जाने के बाद से इसका असर गंभीर रूप से अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस मुद्दे को 'बड़ी समस्या' करार देते हुए स्वदेशी जागरण मंच ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) द्वारा रॉयल्टी और तकनीकी फीस के नाम पर 'बहुमूल्य' विदेशी मुद्रा के देश से बाहर जाने पर चिंता व्यक्त की।

स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने एक बयान में कहा, ''आज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) का उनकी मूल कंपनी यूनिलीवर को किए जाने वाले रॉयल्टी भुगतान को 2.65 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.45 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो कि तीन वर्षों में 2025 तक 80–आधार अंकों की वृद्धि है।''

डॉ. महाजन ने कहा, ''इस निर्णय ने एक बार फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बढ़ते रॉयल्टी भुगतान की अनैतिक प्रथा को उजागर किया है, जो आम तौर पर अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और विदेशी मुद्रा के प्रवाह और विशेष रूप से रुपये के मूल्यह्रास को प्रभावित करता है।''

https://www.ibc24.in/country/ban-on-royalty-payments-by-multinational-companies-sjm-1377108.html

स्वदेशी जागरण मंच का सुझाव– सरकारी बैंकों को न बेचे सरकार

स्वदेशी जागरण मंच के सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन का कहना है कि भारत सरकार को पब्लिक सेक्टर के बैंकों को नहीं बेचना चाहिए। महाजन का तर्क है कि इन बैंकों का इस्तेमाल जन धन योजना (फाइनेंशियल इनक्लुजन प्रोग्राम) जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए हो रहा है, ऐसे में इन बैंकों को नहीं बेचा जाना चाहिए। महाजन ने मनीकंट्रोल के साथ इंटरव्यू में यह बातें कहीं।

महाजन ने आगे कहा, "पब्लिक सेक्टर के बैंकों को पब्लिक सेक्टर में बने रहना चाहिए। इन्हें बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए। हमने यह बार–बार कहा है। निजी क्षेत्र के बैंकों ने कौन से महान कार्य किए हैं?" बैंकों के निजीकरण का विपक्षी दलों ने भी पहले काफी विरोध किया है। स्वदेशी जागरण मंच की इस टिप्पणी से विपक्ष को बल मिल सकता है। मनीकंट्रोल ने बताया है कि सरकार बहुत कंजर्वेटिव डिस–इन्वेस्टमेंट टारगेट तय कर सकती है और बैंकों और बीमा कंपनियों के निजीकरण को टाल सकती है। वर्तमान बजट खास है क्योंकि यह 2024 के आम चुनावों से पहले आखिरी पूर्ण बजट है।

1 फरवरी, 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021–22 में आईडीबीआई बैंक के साथ–साथ पब्लिक सेक्टर के दो बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव दिया था। वर्तमान में भारत में एक दर्जन पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। इसके अलावा, भारत में 21 प्राइवेट बैंक, एक दर्जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और चार पेमेंट बैंक के साथ ही 40 से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 40 से अधिक विदेशी बैंक हैं। सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया में है। लेनदेन 2023–24 की पहली छमाही में पूरा होने की संभावना है।

महाजन ने आगे कहा कि समस्या मैनेजमेंट को लेकर है, ना कि मालिकाना हक को लेकर। स्वामित्व किसके पास है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप इसके मालिक हों या मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बैंकों को अच्छे से चलाना चाहिए।' एसेट क्वालिटी रिव्यू और महामारी के दौरा न बैंकों के कैपिटलाइजेशन के बाद हाल के वर्षों में भारतीय बैंकों के बैड लोन कम हुए हैं। मार्च 2022 में सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का ग्रॉस एनपीए रेश्यो मार्च 2021 में 7.3 प्रतिशत से कम होकर 5.8 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान नेट एनपीए 8 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत हो गया।

https://hindi.moneycontrol.com/news/business/budget/budget-2023-rss-affiliate-swadeshi-jagran-manch-against-psb-divestment-1011791.html

भारत के लिए बहुत उपयोगी नहीं डब्ल्यूईएफः स्वदेशी जागरण मंच

स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व इकोनॉमिक फोरम में दुनिया भर के कारोबारियों से लेकर विश्व स्तर के नेता पहुंचे हुए हैं। भारत की ओर से भी कई केन्द्रीय मंत्री इसमें भाग लेने पहुंचे हुए हैं जबकि कई और जा सकते हैं। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि ये भारत के लिए ज्यादा उपयोगी हो ऐसी समझ हमारी नहीं है। हां, ये फोरम अपनी समझ विकसित करने का एक माध्यम है जिसे हम गलत नहीं मानते हैं।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक अश्वनी महाजन बताते हैं कि ये जो फोरम है ये बिजनेस का ग्लोबल फोरम है, इसमें अधिकांश कॉरपोरेट, एमएनसी, भाग लेते हैं। उनका कहना है कि कैपिटल रिसोर्स और एमएनसी अपने बारे में विचार करें तो उनके लिए ये ठीक हो सकता है लेकिन भारत के लिए ये ज्यादा उपयोगी हो ऐसी समझ हमारी नहीं है। वो आगे कहते हैं कि फिर भी दुनिया में जो कंफीग्रेशन होती हैं उसमें भागीदारी करना उसमें गलत नहीं है। दुनिया

में जो फोर्सेज हैं वो क्या कर रही हैं, उनके बारे में जानकारी लेना और वहां अपनी समझ को विकसित करना उस दृष्टि से ये भारत के इंगेजमेंट के बारे में हो सकता है। लेकिन इसमें जो फोर्सेज काम कर रही होती हैं उनके पाइंट ऑफ व्यू को समझना जरूरी है।

अश्वनी महाजन कहते हैं कि देखिए इसमें हासिल होने जैसा कुछ नहीं होता है। इसमें समझौते नहीं होते हैं। इसमें कुल मिलाकर आप ट्रेड या इकोनॉमी से जुड़े मामलों को लेकर अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में किस बारे में विचार चल रहा है।

देखिए जो भी निवेश होते हैं आंतरिक और बाहरी वो आर्थिक मुददों के आधार पर होते हैं। अफ्रीका जैसे देश हैं या बनाना रिपब्लिक हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है जहां निवेशक बहुत आकर्षित नहीं होते हैं, अगर वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मे चले जाएंगे तो उन्हें कोई निवेश नहीं मिलने वाला है। जैसे मेला होता है और वहां सबलोग जाते हैं। ये एक अंतरराष्ट्रीय मेला है, एक दूसरा मेला भी लगता है दुनिया में जिसे वर्ल्ड सोशल फोरम कहा जाता है। ये जो सारी कैपिटेलिस्ट फोर्सेज हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाती हैं और जो सोशलिस्ट जो लेफटिस्ट फोर्सेस हैं या कई बार वो लोग जो रोजगार, बेरोजगारी जैसे विषयों को लेकर सामाजिक सरोकार रखते हैं वो भी वर्ल्ड सोशल फोरम में जाती हैं। ये केवल समझ विकसित करने का मंच हैं।

https://www.bwhindi.com/interviews-news/we-do-not-think-that-this-world-economic-foram-will-be-more-useful-for-india-swadeshi-jagran-manch-54477.html

स्वावलंबी भारत अभियानः 350 से अधिक जिलों में खुले केंद्र

स्वावलंबी भारत अभियान में ऑनलाइन समारोह में देशभर में 350 से अधिक जिला रोजगार सृजन केंद्रों की स्थापना की गई। डिजिटल माध्यम से एक साथ इनकी शुरुआत की गई। इस दौरान स्वावलंबी भारत अभियान के समन्वयक डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा ने कहा, युवा लंबे समय तक नौकरी के लिए समय खराब करने की जगह नौकरी देने वाला बनने के लिए आगे आएं। अभियान के सह समन्वयक डॉ. राजीव कुमार ने अभियान एवं जिला रोजगार सृजन केंद्रों की संकल्पना को बताया। 17 फरवरी तक देशभर के 400 से अधिक जिला केंद्रों पर जिला रोजगार सृजन केंद्र स्थापित कर दिए जाएंगे। 17 से 19 फरवरी को सभी केंद्रों की कार्यशाला का आयोजन दिल्ली में होगा। आयोजन में झाबुआ से स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी दिलीप जोशी, अनिल पोरवाल, मनोज उपाध्याय, राजू धानक, मोहन यादव आदि मौजूद थे।

https://www.bhaskar.com/local/mp/jhabua/news/centers-started-in-more-than-350-districts-in-the-country-under-self-reliant-india-campaign-130893373.html

क्या होती है शॉर्ट सेलिंग तथा कैसे दिया जाता है इसे अंजाम?

शॉट सेलिंग या शॉटिंग शेयर बाजार की एक बाजार की एक एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जिसके जरिए एक ट्रेडर बाजार में भाग लेता है। हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट सामने आने के बाद से ये शब्द लगातार चर्चा में बना हुआ है। हिंडनबर्ग की ओर से रिपोर्ट जारी कर कहा गया था कि उसने यूएस ट्रेडेड बॉन्ड्स और नॉन–इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में शॉर्ट पोजिशन बनाई हुई है। ऐसे में लोगों में मन नें सवाल उठ रहा है कि आखिर शॉट सेलिंग होती क्या है और इससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं।

शॉर्ट सेलिंग एक काफी पेचीदा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है। इसके तहत बाजार में कारोबार करने वाला ट्रेडर शेयरों को पहले ऊंचे कीमत पर बेच देता है और फिर निचले भाव पर खरीदता है और इन दोनों के बीच में होने वाला अंतर ट्रेडर का मुनाफा होता है। बाजार नियामक सेबी की ओर से दी गई परिभाषा के अनुसार, शॉर्ट सेलिंग वह होती है, जिसमें ट्रेडर अपने पास न होते हुए भी शेयर को बेच देता है। ये बाजार में मार्जिन पर बेचे जाते हैं और बाद में कीमत नीचे गिरने पर खरीद लिए जाते हैं।

बाजार में शॉर्ट सेलिंग तीन तरीके से हो सकते है। पहला– कैश, दूसरा– ऑप्शन, तीसरा– फ्यूचर्स। यहां ध्यान देनी वाली बात है कि कैश में केवल इंट्रडे शॉर्ट सेलिंग हो सकती है, जबकि ऑप्शन और फ्यूचर्स में लिए गए शॉट्स को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। बता दें, शॉर्ट सेलिंग पर नियामक कड़ी निगरानी रखता है और कोई भी गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई करता है।

उदाहरण– मान लीजिए श्याम नाम का एक ट्रेडर है और उसे लगता है कि एबीसी कंपनी के शेयर का प्राइस अधिक चल रहा है और नीचे आ सकता है। तो फिर वह अपनी सुविधा के अनुसार कैश, ऑप्शन और फ्यूचर्स में से किसी का चयन करके शॉर्ट बना सकता है। याद रहे कि शॉर्ट सेलिंग एक काफी कठिन प्रक्रिया है। इसमें किसी को विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। गलत होने पर आपको ऑप्शन और फ्यूचर्स में 100 प्रतिशत पूंजी का भी नुकसान हो सकता है।

शॉर्ट सेलिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें छोटी अवधि में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसका नुकसान यह है कि शॉर्ट सेलिंग करके कोई भी ग्रुप बनाकर किसी विशेष कंपनी के शेयर को निशाना बना सकता है और नीचे गिरा सकता है। बड़ी मात्रा में शॉर्ट होने से बाजार से अस्थिर होने का खतरा बना रहता है। ❑❑

https://www.jagran.com/business/biz-explained-what-is-short-selling-in-stock-market-all-you-need-to-know-about-23321880.html

स्वावलंबी भारत अभियान

जिला रोजगार सृजन केंद्र

सचित्र झलक

भीलवाड़ा, राजस्थान

बलरामपुर, उ.प्र.

मदुरै, तमिलनाडु

कांचिंग, मणिपुर

बीकानेर, राजस्थान

छिन्दवाड़ा, महाकौशल

वायनाड़, केरल

उदयपुर, राजस्थान

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 फरवरी 2023
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

जिला रोजगार सृजन केंद्र

सचित्र झलक

दिल्ली

गुवाहटी, असम

इम्फाल, मणिपुर

जेसलमेर, राजस्थान

जमशेदपुर, झारखंड

छतरपुर, महाकौशल

पश्चिमी गोदावरी, आंध्र प्रदेश

हापुड़, उत्तर प्रदेश

Advt.

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती